

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]
No. 32]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 12, 1978/श्रावण 21, 1900
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 12, 1978/SRAVANA 21, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

प्रवेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1978

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1978

का० भा० 2292 :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली प्रशासन के परामर्श से श्री ज्ञान चन्द जैन, सचिव (विधि तथा न्यायिक), दिल्ली प्रशासन को उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख से अगले आदेशों तक श्री एम० के० चावला के स्थान पर, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकार के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है।

[सं० 154/दिल्ली/78]

टी० नागरथनम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 24th July, 1978

S.O. 2292.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Delhi Administration, hereby nominates Shri Gian Chand Jain, Secretary (Law and Judicial) Delhi Administration, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Delhi with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri M. K. Chawla.

[No. 154/DL/78]

T. NAGARATHANAM, Secy.

का० भा० 2293 :—निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो चुका है कि—में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 12-फरीदकोट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जीता राम, गांव ब डा० रामनगर तहसील मुक्तसर, जिला फरीदकोट पंजाब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जीता राम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० पंजाब-लो० सं० 12/77]

बी० नागामुहम्मद, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th July, 1978

S.O. 2293.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jeeta Ram, Village and P. O. Ram Nagar, Tahsil Muktsar, District Faridkot Punjab who was a contesting candidate for general election to the House of the People from 12-Faridkot held in March 1977 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice, has not given any satisfactory reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jeeta Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-HP/12/77]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

(c) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, any offence mentioned in clauses (a) and (b) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/3/75-AVD. II]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1978

का० प्र० 2295 :—आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण प्रदेश, 1975 (सा० का० नि० 285ई, तारीख 19 मई, 1975) के पैरा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत सरकार विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं विधि सहायकार, श्री पी० एच० रामचन्द्रानी को उनके द्वारा अपने पद का कार्य सम्भालने की तारीख से आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण का सचिव नियुक्त करते हैं।

[सं० एस-21011/22/77-एस० आर०]

प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 2nd August, 1978

S.O. 2295.—In exercise of the powers conferred by paragraph 3 of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975 (G.S.R. 285E, dated 19th May, 1975), the President is pleased to appoint Shri P. H. Ramchandani, Joint Secretary and Legal Adviser, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Government of India, as Member of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal with effect from the date he takes over charge of office.

[No. S-21011/22/77-SR]

P. P. SHRIVASTAV, Jt. Secy.

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1978

आय-कर

का० प्र० 2296 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि अधिसूचना सं० 56, फा० सं० 10/63/65-आई० टी० ए०-II तारीख 30 जून, 1965 द्वारा सरकार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) (ii) के अधीन दिया गया अनुमोदन, विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली की सिफारिश पर 26 नवम्बर, 1977 से वापस लिया जाता है।

[सं० 2237/फा० सं० 203/33/78-आई० टी० ए०-II]

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th March, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2296.—It is hereby notified for general information that the approval given under section 35(1) (ii) of the Income-tax Act, 1961 to Sardar Patel Institute of Economic & Social Research, Ahmedabad, by notification No. 56, F No. 10/63/65-ITA, II dated 30th June, 1965 is withdrawn with effect from 26th November, 1977 on the recommendation of the prescribed authority, the Department of Science & Technology, New Delhi.

[No. 2237/F. No. 203/33/78-ITA, II]

राष्ट्र मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1978

का० प्र० 2294 :—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराध निर्धारित करती है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाता है, नामतः—

- (क) सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धाराओं 35-ए, 35-डी, 35-ई, और 35-एफ के अधीन बंढनीय अपराध;
- (ख) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 27-सी के अधीन बंढनीय अपराध; और
- (ग) खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी अपराध के संबंध में या उससे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों तथा षड्यंत्रों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न हुई वैसी कार्यवाही के दौरान किया गया अन्य कोई अपराध।

[संख्या 228/3/75-एजीडी-II]

टी० के० सुब्रमणियन, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 31st July, 1978

S.O. 2294.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely :—

- (a) Offences punishable under sections 35-A, 35-D, 35-E and 35-F of the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);
- (b) Offences punishable under section 276-C of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961); and

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1978

आय-कर

का० आ० 2297 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था की आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

- (i) यह कि उक्त संस्था, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक् से रखेगी।
- (ii) उक्त संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को अर्पित: प्रति वर्ष 15 मई तक ऐसे प्रारूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

मानक राम मेधराज हृदय अस्पताल और हृदयवाहिका अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई।

यह अधिसूचना 15 मार्च, 1978 से 14 मार्च, 1980 तक के दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगी।

[सं० 2280/का० सं० 203/62/78 आई० टी० ए० II]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

New Delhi, the 26th April, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2297.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

- (i) that the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.
- (ii) that the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 15th May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

Nanikram Menghraj Heart Hospital and Cardiovascular Research Centre, Bombay.

This notification is effective for a period of two years from 15-3-1978 to 14-3-1980.

[No. 2280/F. No. 203/62/78-ITA. II]

J. P. SHARMA, Director.

वार्षिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1978

का० आ० 2298 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उप-खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् 22 जुलाई, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तथा

21 जुलाई, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, एतद् द्वारा श्री बी० वी० सोनालकर को बैंक आफ इण्डिया के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित) के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9(17)/76 बी० प्रो० I]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 22nd July, 1978

S.O. 2298.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri B. V. Sonalkar, as a whole-time Director (designated as the Executive Director) of the Bank of India for the period commencing on 22nd July, 1978 and ending with 21st July, 1981.

[No. F. 9/17/78-BO. I]

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1978

का० आ० 2299 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (च) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद, एतद् द्वारा, प्रोफेसर एस० आर० बिजोर, प्रबन्ध सलाहकार, 31-लोयाला लेफाउट, बिसटोरिया रोड, बंगलोर (कर्नाटक), को 24 जुलाई, 1978 से प्रारम्भ होकर, 23 जुलाई, 1981 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/34/77-बी० प्रो०-I]

New Delhi, the 24th July, 1978

S.O. 2299.—In pursuance of sub-clause (f) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Prof. S. R. Bijoor, Management Consultant, 31, Loyala Layout, Victoria Road, Bangalore (Karnataka) as a Director of the Indian Overseas Bank for a period of three years commencing on the 24th day of July, 1978 and ending with the 23rd day of July, 1981.

[No. F. 9/34/77-BO. I]

का० आ० 2300 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उप-खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् 26 जुलाई, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तथा 9 फरवरी, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, एतद् द्वारा श्री डी० सी० गुप्ता को पंजाब नेशनल बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित) के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9(17)/78 बी० प्रो० I (1)]

S.O. 2300.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri D. C. Gupta, as a whole-time Director (designated as the Executive Director) of the Punjab National Bank for the period commencing on 26th July, 1978 and ending with 9th February, 1980.

[No. F. 9/17/78-BO. I (1)]

का० आ० 2301 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उप-खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् 24 जुलाई, 1978 से प्रारम्भ होने वाली

तथा 19 जनवरी, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, एतद्द्वारा श्री बी०एम० शुक्ल को बैंक आफ बड़ोदा के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित) के रूप में नियुक्त करती है।
[सं० एक० 9/17/78-बी०ओ० I (2)]

S.O. 2301.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri B. M. Shukla, as a whole-time Director (designated as the Executive Director) of the Bank of Baroda for the period commencing on 24th July, 1978 and ending with 19th January, 1981.

[No. F. 9/17/78-BO. I (2)]

क्र०आ०. 2302 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् 24 जुलाई, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तथा 23 जुलाई, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, एतद्द्वारा श्री जे० एन० पाठक को यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित) के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एक० 9/17/78-बी०ओ० I (3)]

S.O. 2302.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri J. N. Pathak, as a whole-time Director (designated as the Executive Director) of the United Commercial Bank for the period commencing on 24th July, 1978 and ending with 23rd July, 1981.

[No. F. 9/17/78-BO. I (3)]

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1978

क्र०आ० 2303—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा श्री सी० ई० कामथ को, 3 सितम्बर, 1978 से प्रारम्भ होकर 2 सितम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये केनरा बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एक० 9/19/78-बी०ओ०-1(1)]

New Delhi, the 26th July, 1978

S.O. 2303.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri C. E. Kamath as the Managing Director of the Canara Bank for a further period commencing on 3rd September, 1978 and ending with 2nd September, 1981.

[No. F. 9/19/78-BO. I(1)]

क्र०आ० 2304—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री सी० ई० कामथ को, जिन्हें 3 सितम्बर, 1978 से केनरा बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है,

उसी तारीख से केनरा बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एक० 9/19/78-बी०ओ०-1(2)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 2304.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri C. E. Kamath, who has been re-appointed as Managing Director of the Canara Bank with effect from 3rd September, 1978 to be the Chairman of the Board of Directors of the Canara Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/19/78-BO. I(2)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1978

क्र० आ० 2305 :—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 8) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के अध्यक्ष श्री जेम्स एस० राज को श्री एच० टी० पारेख के स्थान पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक के रूप में तत्काल नामित करती है।

[सं० एक० 10 (77)/आई० एक० 1/78]

बी० सी० पटनायक, उप सचिव

New Delhi, the 28th July, 1978

S.O. 2305.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri James S. Raj, Chairman, Industrial Credit and Investment Corporation of India, as the director of the Industrial Development Bank of India with immediate effect vice Shri H. T. Parekh.

[No. F. 10(77)/IF. 1/78]

B. C. PATNAIK, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1978

क्र० आ० 2306 :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री मृणाल वैश्य को श्री जी० सी० कालिता के स्थान पर प्रागज्योतिष गांवजिया बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 14 अगस्त, 1978 से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि की उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री मृणाल वैश्य अध्यक्ष पद भार संभालेंगे।

[संख्या एक० 3/20/77-प्रार० प्रार० बी०]

सी० प्रार० बिश्वास, उप सचिव

New Delhi, the 29th July, 1978

S.O. 2306.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Mrinal Baishya as the Chairman of the Pragjyotish gaonlia Bank, vice Shri G. C. Kalita and specifies the period commencing on the 14th August, 1978 and ending with 31st December, 1978 as the period for which the said Shri Mrinal Baishya shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-20/77-RRB]

C. R. BISWAS, Dy. Secy.

(आयकर आयुक्त कार्यालय, विदर्भ, नागपुर)

नागपुर, 30 जून, 1978

कां. प्रां. 3307:—नीचे दी गई सूची में वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान निर्धारितियों के नाम और अन्य विवरण दिखाए गए हैं। इस सूची की अनुसूची I में ऐसे व्यक्ति (इन्डिविजुअल) और हिन्दू अविभक्त परिवार (एच० यू० एफ०) जिनकी आय 2 लाख रुपया से अधिक निर्धारित की गई है, उन्हें दिखाया गया है और अनुसूची-II में ऐसी फर्म व्यक्ति समुदाय (ए० प्रो० पी०) और कंपनियां जिनकी आय 10 लाख रु० से अधिक निर्धारित की गई है, दिखाया गया है। इसमें (i) में हैसियत (स्टेटस) बताई गई है और व्यक्ति के लिए "व्य", हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए "हिम्प", पंजीकृत फर्म के लिए "फर्म", व्यक्ति समुदाय के लिए "व्यस" और कंपनियों के लिए "क" से हंशित किया गया है और (ii) में निर्धारित वर्ष, (iii) में विवरणी में दर्शायी गई आय, (iv) में निर्धारित आय, (v) में वेयर, (vi) में निर्धारितों द्वारा भरा गया कर बताया गया है:—

अनुसूची-I

1. श्री हाजी सत्तार, द्वारा मै० हाजी लतीफ गनी कच्छी, मोसिम-पूरा, नागपुर—(i) व्य (ii) 75-76 (iii) रु० 2,56,704/- (iv) 2,59,210/- (v) रु० 1,73,722/- (vi) 1,73,722/-
2. श्री रमेशचन्द्र लोहया, कामठी (i) हिम्प (ii) 70-71 (iii) शून्य (iv) रु० 2,21,580/- (v) रु० 98,384/- (vi) कुछ नहीं।
3. श्री रमेश चन्द्र लोहया, कामठी (i) हिम्प (ii) 69-70 (iii) कुछ नहीं (iv) रु० 3,24,688/- (v) रु० 64,607/- (vi) कुछ नहीं।
4. श्री एच० एल० सुलतानी, भागीदार मै० अलाहउद्दुल्लाह इलेक्ट्रिकल स्टोर्स, नागपुर (i) व्य (ii) 77-78 (iii) रु० 2,40,890/- (iv) रु० 2,42,490/- (v) रु० 1,37,163/- (vi) रु० 1,37,163/-
5. श्री अश्वरूपी हसनमल्ली, इतबारी, नागपुर (i) व्य (ii) 75-76 (iii) रु० 2,92,340/- (iv) रु० 3,07,445/- (v) रु० 2,11,116/- (vi) रु० 2,07,600/-
6. श्री अब्दुल्लाभाई हसनमल्ली, इतबारी, नागपुर (i) व्य (ii) 75-76 (iii) रु० 2,85,500/- (iv) रु० 2,93,136/- (v) रु० 2,01,016/- (vi) रु० 1,95,160/-
7. श्रीमती विमला देवी बजाज, घर्घा (i) व्य (ii) 75-76 (iii) रु० 2,72,990/- (iv) रु० 2,72,990/- (v) रु० 1,81,976/- (vi) रु० 1,81,976/-
8. श्री भगवान दत्ता पुरोहित, भागीदार मै० पुरोहित एण्ड कं० घाट रोड नागपुर (i) व्य (ii) 77-78 (iii) रु० 2,60,310/- (iv) रु० 2,62,370/- (v) रु० 1,52,225/- (vi) रु० 1,51,601/-
9. श्री बनवारी लाल पुरोहित, भागीदार मै० पुरोहित एण्ड कं० घाट रोड, नागपुर (i) व्य (ii) 77-78 (iii) रु० 3,00,849/- (iv) रु० 3,01,860/- (v) रु० 1,78,533/- (vi) रु० 1,78,533/-
10. श्री अशोक कुमार पुरोहित, भागीदार मै० पुरोहित एण्ड कं० घाट रोड, नागपुर (i) व्य (ii) 77-78 (iii) रु० 2,39,020/- (iv) रु० 2,39,870/- (v) रु० 1,37,184/- (vi) रु० 1,41,264/-

अनुसूची-II

1. मै० बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि० बल्लारपुर (i) क (ii) 74-75 (iii) रु० 3,91,42,590/- (iv) रु० 4,07,29,115/- (v) रु० 2,35,21,052/- (vi) रु० 2,35,21,052/-
2. मै० बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि० बल्लारपुर (i) क (ii) 75-76 (iii) रु० 6,10,68,960/- (iv) रु० 6,49,48,650 (v) रु० 3,67,80,627/- (vi) रु० 3,67,80,627/-
3. मै० बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि० बल्लारपुर (i) क (ii) 76-77 (iii) रु० 13,04,28,900/- (iv) रु० 13,48,92,810/- (v) रु० 7,71,23,220/- (vi) 7,71,23,220/-
4. मै० मैट्रल प्राक्लिसेस मंगलजि और कं० लि० नागपुर (i) विदेशी क (ii) 74-75 (iii) रु० 8,88,560/- (iv) रु० 10,12,290/- (v) रु० 8,00,910/- (vi) 8,00,910/-

नीचे दी गई सूची में वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान जिन व्यक्तियों पर कम से कम 5000/- रु० की शास्ति (पेनाल्टी) लगाई गई थी, उनके नाम दिखाए गए हैं। इसमें (i) में हैसियत (स्टेटस) बताई गई है और इसमें व्यक्ति के लिए "व्य", हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए "हिम्प", पंजीकृत फर्म के लिए "फर्म", अविभक्त फर्म के लिए "अफर्म", कंपनी के लिए "क" और सहकारी समिति (कोऑपरेटिव सोसायटी) के लिए "सस" दिखाया गया है, (ii) में निर्धारित वर्ष, (iii) में शास्ति (पेनाल्टी) की रकम, (iv) में द्वारा जिसके अन्तर्गत शास्ति लगाई गई थी, दिखाए गए हैं:—

1. विदर्भ बोर्ड मिल्स लि० घाट रोड, नागपुर (i) क (ii) 73-74 (iii) रु० 17,063/- (iv) 271 (i) (ए)
2. विदर्भ बोर्ड मिल्स लि० घाट रोड, नागपुर (i) क (ii) 74-75 (iii) रु० 9,790/- (iv) 271 (i) (ए)
3. श्री के० डी० सतपुते, काटन मार्केट, नागपुर (i) व्य (ii) 75-76 (iii) रु० 8,000/- (iv) 271 (i) (सी)
4. मै० लोहया ब्रह्म, कामठी (i) अफर्म (ii) 73-74 (iii) रु० 1,00,000/- (iv) 271 (i) (सी)
5. मै० लोहया ब्रह्म, कामठी (i) अफर्म (ii) 73-74 (iii) रु० 10,000/- (iv) 271 (i) (सी)
6. मै० बीडी अलाहउद्दुल्लाह टोबेको प्राइवेट्स प्रा० लि०, कामठी (i) क (ii) 73-74 (iii) रु० 20,453/- (iv) 271 (i) (ए)
7. मै० बीडी अलाहउद्दुल्लाह टोबेको प्राइवेट्स प्रा० लि०, कामठी (i) क (ii) 73-74 (iii) रु० 15,000/- (iv) 271 (i) (सी)

[सं० तक्र०/287/42-ए/77-78]

(Office of the Commissioner of Income Tax, Vidharba, Nagpur)

Nagpur, the 30th June, 1978

S.O. 2307.—Following is the list of the names and other particulars of the assessee namely individuals and H. U. Fs. assessed on an income over Rs. 2 lakhs in Schedule I, and Firms, A. O. Ps. and Companies assessed on an income over Rs. 10 lakhs in Schedule II, during the financial year 1977-78: (i) Indicates Status 'T' for Individuals 'H' for Hindu Undivided families 'R. F.' for Registered Firms, 'AOP' for Association of persons and Co., for Companies (ii) for assessment year (iii) for Income returned (iv) for Income assessed (v) for Tax payable (vi) for Tax paid by the assessee :

SCHEDULE 1

1. Shri Haji Sattar, C/o M/s Haji Latif Gani Kachhi, Mominpura, Nagpur (i) I. (ii) 75-76 (iii) Rs. 2,56,764 (iv) Rs. 2,59,210 (v) Rs. 1,73,722 (vi) Rs. 1,73,722.
2. Shri Rameshchandra Loiya, Kamptee (i) H (ii) 70-71 (iii) Nil. (iv) Rs. 2,21,580 (v) Rs. 98,384 (vi) Nil.
3. Shri Rameshchandra Loiya, Kamptee (i) H (ii) 69-70 (iii) Nil (iv) Rs. 3,24,668 (v) Rs. 64,607 (vi) Nil.
4. Shri H. L. Multani, P/o M/s Allied Electrical Stores, Nagpur (i) I (ii) 77-78 (iii) Rs. 2,40,890 (iv) Rs. 2,42,490 (v) Rs. 1,37,163 (vi) Rs. 1,37,163.
5. Shri Asgharali Hasanali, Itwari, Nagpur (i) I (ii) 75-76 (iii) Rs. 6,10,68,960 (iv) Rs. 6,49,48,650 (v) Rs. 2,11,116 (vi) Rs. 2,07,600.
6. Shri Abdulla Bhai Hasanali, Itwari, Nagpur (i) I (ii) 75-76 (iii) Rs. 2,85,500 (iv) Rs. 2,93,156 (v) Rs. 2,01,016 (vi) Rs. 1,95,160.
7. Smt. Vimladevi Bajaj, Wardha (i) I (ii) 75-76 (iii) Rs. 2,72,990 (iv) Rs. 2,72,990 (v) Rs. 1,81,976 (vi) Rs. 1,81,976.
8. Shri Bhagwandas Prohit, P/o M/s Prohit & Co., Ghat Road, Nagpur (i) I (ii) 77-78 (iii) Rs. 2,60,310 (iv) Rs. 2,62,370 (v) Rs. 1,52,225 (vi) Rs. 1,51,601.
9. Shri Banwarilal Prohit, P/o M/s Prohit & Co., Ghat Road, Nagpur (i) I (ii) 77-78 (iii) Rs. 3,00,849 (iv) 3,01,860 (v) Rs. 1,78,533 (vi) Rs. 1,78,533.
10. Shri Ashok Kumar Prohit, P/o M/s Prohit & Co., Ghat Road, Nagpur (i) I (ii) 77-78 (iii) Rs. 2,39,020 (iv) Rs. 2,39,870 (v) Rs. 1,37,184 (vi) Rs. 1,41,264.

SCHEDULE II

1. M/s Ballarpur Industries Ltd. Ballarpur (i) Co., (ii) 74-75 (iii) Rs. 3,91,42,590 (iv) Rs. 4,07,29,115 (v) Rs. 2,35,21,052 (vi) Rs. 2,35,21,052.
2. M/s Ballarpur Industries Ltd., Ballarpur (i) Co. (ii) 75-76 (iii) Rs. 6,10,68,960 (iv) Rs. 6,49,48,650 (v) Rs. 3,67,80,627 (vi) Rs. 3,67,80,627.
3. M/s Ballarpur Industries Ltd. Ballarpur (i) Co., (ii) 76-77 (iii) Rs. 13,04,28,900 (iv) Rs. 13,48,92,810 (v) Rs. 7,71,23,220 (vi) Rs. 7,71,23,220.
4. M/s Central Provinces Maganese Ore Co., Ltd., Nagpur (i) F. Co., (ii) 74-75 (iii) Rs. 8,88,560 (iv) Rs. 10,12,290 (v) Rs. 8,00,910 (vi) Rs. 8,00,910.

Following is the list of persons on whom penalty not less than Rs. 5,000 was imposed during the financial year 1977-78 : (i) Indicating Status 'I' for Individual 'H' for HUF 'R.F.' for Registered Firm 'URF' for Un-registered Firm 'Co.' for Companies and 'STY' for Co-operative Society (ii) for assessment year (iii) Amount of penalty (iv) Section under which penalty was imposed :

1. Vidarbha Board Mills Ltd., Ghat Road, Nagpur (i) Co., (ii) 73-74, (iii) Rs. 17,063, (iv) 271(1)(a).
2. Vidarbha Board Mills Ltd., Ghat Road, Nagpur (i) Co., (ii) 74-75, (iii) Rs. 9,790, (iv) 271(1)(a).
3. Shri K. D. Satpute, Cotton Market, Nagpur (i) I. (ii) 75-76, (iii) Rs. 8,000, (iv) 271(1)(c).
4. M/s. Loiya Brothers Kamptee (i) URF, (ii) 73-74, (iii) Rs. 1,00,000, (iv) 271(1)(c).
5. M/s. Loiya Brothers, Kamptee (i) URF, (ii) 73-74, (iii) Rs. 10,000, (iv) 271(1)(b).

6. M/s. Bedl Allied and Tobacco Products P. Ltd., Kamptee (i) Co., (ii) 73-74, (iii) Rs. 20,453, (iv) 271(1)(a).

7. M/s. Bidi Allied and Tobacco Products P. Ltd., Kamptee (i) Co., (ii) 73-74, (iii) Rs. 15,000 (iv) 271(1)(b).

[No. Tech/287/42-A/77-78]

क्र.सं. 2308:—विनीय वर्ष 1977-78 के दौरान रु० 10 लाख से अधिक के धन (वैध) पर जिन व्यक्तियों का निर्धारण हुआ है, उनकी सूची नीचे दी गई है। (गकेत) (i) में प्रास्थिति (स्टेटस) बताई गई है और इसमें व्यक्ति के लिए "व्य" और हिन्दू अधिभक्त परिवार के लिए "हिम्प" (ii) विवरणों में दर्शाया गया धन/ निर्धारित धन (iii) निर्धारित द्वारा देयकर/निर्धारित द्वारा भरा गया कर :

1. श्री ग्वालदास मोहता, हिमनबाद (i) हिम्प (ii) रु० 10,19,500/ रु० 10,58,900/- (iii) रु० 39,710/- रु० 39,710/-
2. श्री श्रीकुमार बजाज, वर्धा (i) व्य (ii) रु० 36,97,400/- रु० 36,70,130/- (iii) रु० 1,02,203/- रु० 1,02,203/-
3. श्री शेखरकुमार बजाज, वर्धा (i) हिम्प (ii) रु० 12,08,600/- रु० 12,03,000 (iii) रु० 28,353/- रु० 28,353/-
4. श्रीमती कुमुद बजाज, वर्धा (i) व्य (ii) रु० 10,55,500/- रु० 10,51,600 (iii) रु० 15,039/- रु० 15,039/-
5. श्रीमती मिनाश्री बजाज, वर्धा (i) व्य (ii) रु० 11,42,100/ रु० 11,37,800 (iii) रु० 17,195/- रु० 17,195/-
6. श्री रामकृष्ण बजाज, वर्धा (i) हिम्प (ii) रु० 12,52,500/ रु० 12,52,500 (iii) रु० 55,200/- रु० 55,200/-
7. श्री रामकृष्ण बजाज, वर्धा (i) हिम्प (ii) रु० 16,29,700/ रु० 16,20,000 (iii) रु० 42,950/- रु० 42,950/-
8. श्री मधुरकुमार बजाज, वर्धा (i) व्य (ii) रु० 12,95,700/ रु० 12,89,200 (iii) रु० 31,373/- रु० 31,373/-
9. श्री शेखर कुमार बजाज, वर्धा (i) व्य (ii) रु० 13,26,100/ रु० 13,20,800 (iii) रु० 21,771/- रु० 21,771
10. श्रीमती उमादेवी भगरवाल, वर्धा (i) व्य (ii) रु० 10,00,500/ रु० 10,70,000 (iii) रु० 17,105/- रु० 17,105/
11. श्रीमती उमादेवी भगरवाल, वर्धा (i) व्य (ii) रु० 10,12,000/ रु० 10,85,200 (iii) रु० 23,408/- रु० 23,408/-
12. श्रीमती उमादेवी भगरवाल, वर्धा (i) व्य (ii) रु० 10,42,600/ रु० 11,11,600 (iii) रु० 24,464/ रु० 24,464/
13. श्री राहुलकुमार बजाज, वर्धा (i) हिम्प (ii) रु० 11,46,600/ रु० 11,46,600 (iii) रु० 46,734/- रु० 46,734/-
14. श्री एच० एल० ओहरी, बल्लारपुर (i) व्य (ii) रु० 10,54,000/ रु० 11,17,290 (iii) रु० 24,690/- रु० 21,310/-
15. श्री एच० एल० ओहरी, बल्लारपुर (i) हिम्प (ii) रु० 7,23,798/ रु० 11,27,860 (iii) रु० 16,837/ रु० 13,252/-
16. श्री एच० एल० ओहरी, बल्लारपुर (i) हिम्प (ii) रु० 7,67,631/- रु० 10,85,590 (iii) रु० 17,520/ रु० 16,735/-
17. श्री एच० एल० ओहरी, बल्लारपुर (i) हिम्प (ii) रु० 8,56,842/ रु० 12,72,505 (iii) रु० 23,175/ रु० 44,000/-
18. श्री एच० एल० ओहरी, बल्लारपुर (i) हिम्प (ii) रु० 6,64,130/ रु० 15,29,540 (iii) रु० 67,365/ रु० 61,680/-
19. श्री एच० एल० ओहरी, बल्लारपुर (i) हिम्प (ii) रु० 4,21,803/ रु० 13,53,030 (iii) रु० 63,240/ रु० 40,430/-

[सं. तक/287/42-ए/77-78]

श्री० चिवम्बरम, प्रायकर प्रायुक्त

S.O. 2308.—Following is the list of persons who have been assessed to net wealth over Rs. 10 lakhs during the financial year 1977-78. (Indications) (i) Status 'I' for Individuals and 'H' for HUF (ii) for wealth returned/wealth assessed (iii) for tax payable by the assessee/Tax paid by the assessee:

1. Shri Gwalidas Mohots, Hinganghat (i) H (ii) Rs. 10,19,500/- Rs. 10,58,900/- (iii) Rs. 39,710/- Rs. 39,710/-.
2. Shri Shirkumar Bajaj, Wardha (i) I (ii) Rs. 36,97,400/- Rs. 36,70,130/- (iii) Rs. 1,02,203/- Rs. 1,02,203/-.
3. Shri Shekharkumar Bajaj, Wardha (i) H (ii) Rs. 12,08,600/- Rs. 12,03,000/- (iii) Rs. 28,353/- Rs. 28,353/-.
4. Smt. Kumud Bajaj, Wardha (i) I (ii) Rs. 10,55,500/- Rs. 10,51,600/- (iii) Rs. 15,039/- Rs. 15,039/-.
5. Smt. Minakshi Bajaj, Wardha (i) I (ii) Rs. 11,42,100/- Rs. 11,37,800/- (iii) Rs. 17,195/- Rs. 17,195/-.
6. Shri Ramkrishna Bajaj, Wardha (i) H (ii) Rs. 12,52,500/- Rs. 12,52,500/- (iii) Rs. 55,200/- Rs. 55,200/-.
7. Shri Ramkrishna Bajaj, Wardha (i) H (ii) Rs. 16,29,700/- Rs. 16,20,000/- (iii) Rs. 42,950/- Rs. 42,950/-.
8. Shri Madhirkumar Bajaj, Wardha (i) I (ii) Rs. 12,95,700/- Rs. 12,89,200/- (iii) Rs. 31,373/- Rs. 31,373/-.
9. Shri Shekharkumar Bajaj, Wardha (i) I (ii) Rs. 13,26,100/- Rs. 13,20,800/- (iii) Rs. 21,771/- Rs. 21,771/-.
10. Smt. Umadevi Agarwal, Wardha (i) I (ii) Rs. 10,00,500/- Rs. 10,70,000/- (iii) Rs. 17,105/- Rs. 17,105/-.
11. Smt. Umadevi Agarwal, Wardha (i) I (ii) Rs. 10,12,000/- Rs. 10,85,200/- (iii) Rs. 23,408/- Rs. 23,408/-.
12. Smt. Umadevi Agarwal, Wardha (i) I (ii) Rs. 11,46,600 Rs. 11,46,600 (iii) Rs. 46,734 Rs. 24,464/-.
13. Shri Rahulkumar Bajaj, Wardha (i) H (ii) Rs. 11,46,600/- Rs. 11,46,600/- (iii) Rs. 46,734/- Rs. 46,734/-.
14. Shri M. L. Ohri, Ballarpur (i) I (ii) Rs. 10,54,000/- Rs. 11,17,290/- (iii) Rs. 24,690/- Rs. 21,310/-.
15. Shri H. L. Ohri, Ballarpur (i) H (ii) Rs. 7,23,798/- Rs. 1,27,860/- (iii) Rs. 16,837/- Rs. 13,252/-.
16. Shri H. L. Ohri, Ballarpur (i) H (ii) Rs. 7,67,631/- Rs. 10,85,590/- (iii) Rs. 17,520/- Rs. 16,733/-.
17. Shri H. L. Ohri, Ballarpur (i) H (ii) Rs. 8,56,842/- Rs. 12,72,505/- (iii) Rs. 23,175/- Rs. 44,000/-.
18. Shri H. L. Ohri, Ballarpur (i) H (ii) Rs. 6,64,130/- Rs. 15,29,540/- (iii) Rs. 67,365/- Rs. 61,680/-.
19. Shri H. L. Ohri, Ballarpur (i) H (ii) Rs. 4,21,803/- Rs. 13,53,030/- (iii) Rs. 63,240/- Rs. 40,430/-.

[No. Tech/287/42-A/77-78]

V. CHIDAMBARAM, Commissioner of Income tax

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1978

क्रा० प्रा० 2309.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नारियल जटा के तंतु के

निर्यात (निरीक्षण) अधिनियम, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम नारियल जटा के तंतु का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नारियल जटा के तंतु के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“7क निरीक्षण फीस

प्रति परेक्षण के लिए न्यूनतम 22.50 रुपये के अधीन रहते हुए निरीक्षण फीस के रूप में नारियल-जटा के तंतु के लिए प्रति गांठ 2.25 रुपये की दर से फीस दी जाएगी। परन्तु निर्धारित न्यूनतम फीस पुनः दबाई हुई गांठों पर लागू नहीं होगी।”

[सं० 6(2)/76नि० नि० तथा नि० उ०]

New Delhi, the 12th August, 1978

S.O. 2309.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Coir Yarn (Inspection) Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Coir Yarn (Inspection) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Coir Yarn, (Inspection Rules, 1966 for rule 7A, the following rule shall be substituted, namely:—

“7A. Inspection Fee.

A fee at the rate of Rs. 2.25 per bale, subject to a minimum of Rs. 22.50 per consignment, shall be paid as inspection fee for Coir Yarn. Provided that the minimum fee prescribed shall not apply to re-pressed bales.”

[No. 6(2)/76-EI&EP]

क्रा० प्रा० 2310.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नारियल जटा की मैटिंगों के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम नारियल-जटा की मैटिंगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन अधिनियम, 1978 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

“6. निरीक्षण फीस: नारियल जटा तथा नारियल से बने पायदानों के लिए फीस निरीक्षण फीस के रूप में निम्नलिखित दरों पर दी जाएगी, अर्थात्:—

- | | |
|--|---|
| (क) नारियल जटा की मैटिंग: चौड़ाई में 2.5 मीटर तथा कम | न्यूनतम 10 रुपये प्रति परेक्षण के अधीन रहते हुए 1.00 रुपये प्रति पैकेट |
| (ख) नारियल जटा की मैटिंग चौड़ाई में 2.5 मीटर से अधिक | न्यूनतम 30 रुपये प्रति परेक्षण के अधीन रहते हुए, 3.00 रुपये प्रति पैकेट |

(ग) नारियल जटा के पाबदान न्यूनतम 6 रुपये प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, 0.60 रुपया प्रति पैकेट।

[सं० 6 (2)/76-नि० नि० तथा नि० उ०]

S.O. 2310.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Coir Matting (Inspection) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Coir Matting (Inspection) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Export of Coir Matting (Inspection) Rules, 1972 for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Inspection Fee : A fee at the following rates shall be paid as inspection fee for coir matting and coir matting mats, namely :—

- | | |
|--|---|
| (a) Coir matting : 2.5 metres and below in width | Rs. 1.00 per packet subject to a minimum of Rs. 10 per consignment. |
| (b) Coir matting : above 2.5 mtr. in width | Rs. 3.00 per packet subject to a minimum of Rs. 30 per consignment. |
| (c) Coir matting mats. | Rs. 0.60 per packet subject to a minimum of Rs. 6 per consignment. |

[No. 6.(2)/76-EI & EP]

का० प्रा० 2311.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण), अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नारियल जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 में और आगे संशोधन के लिए निम्न लिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नारियल जटा से बनी वस्तुओं का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नारियल जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 में नियम 5क के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5क निरीक्षण फीस

प्रति परेषण के लिए न्यूनतम 6 रुपये के अधीन रहते हुए नारियल जटा से बनी वस्तुओं के निरीक्षण के लिए 0.60 रुपया प्रति बंडल की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी।"

[सं० 6(2)/76-नि० नि० तथा नि० उ०]

S.O. 2311.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Coir Products (Inspection) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Coir Products (Inspection) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Coir Products Inspection Rules, 1965, for rule 5A, the following rule shall be substituted, namely :—

"5A. Inspection Fee.—

A fee at the rate of Rs. 0.60 per handle, subject to a minimum of Rs. 6 per consignment, shall be paid as inspection fee for inspection of Coir Products."

[No. 6(2)/76-EI&EP]

का० प्रा० 2312.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार बिना गांठ बंधे नारियल जटा के तंतु के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम बिना गांठ बंधे नारियल जटा के तंतु का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बिना गांठ बंधे नारियल जटा के तंतु के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 में नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7 निरीक्षण फीस

प्रति परेषण के लिए न्यूनतम 15 रुपये के अधीन रहते हुए बिना गांठ बंधे नारियल के तंतु के लिए 1.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी।"

[सं० 6 (2)/76-नि० नि० तथा नि० उ०]

New Delhi, the 12th August, 1978

S.O. 2312.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the export of non-baled Coir Yarn (Inspection) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Non-baled Coir Yarn (Inspection) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the export of Non-baled Coir Yarn (Inspection) Rules, 1972 for rule 7 the following rule shall be substituted namely :—

"7. Inspection Fee.—

A fee at the rate of Rs. 1.50 per quintal, subject to a minimum of Rs. 15 per consignment shall be paid as inspection fee for non-baled Coir Yarn."

[No. 6(2)/76-EI&EP]

आदेश

का० प्रा० 2313.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०प्रा० 4067 तारीख 20 सितम्बर, 1975 में जो भारत के पट्टन की परतदार वस्तुओं के निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित है, निर्यात व्यापार के

विक्रय के लिए नीचे विनिर्दिष्ट ढंग से संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है :

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव तैयार किए हैं तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम ii के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है :

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उससे सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी लोगों की जानकारी के लिए उक्त प्रस्तावों को प्रकाशित करती है।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आप्रोप या सुझाव भेजने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, "बल्ड ट्रेड सेंटर" (प्राइमरी मंजिल) 14/1 बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

उक्त आदेश में, उपाबंध के खण्ड 2 में,—

(1) उप-खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—“बेसिक फैब्रिक में प्रति डेसीमीटर किनारे निर्यात संविदा में निदिष्ट के अनुसार होंगे। प्रति डेसीमीटर किनारों के संबंध में सांख्यिक विनिर्देशों के आधार पर $\pm 7.0\%$ तक की सह्यता स्वीकार की जाएगी।”

(2) उप-खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—“(4) पॉलिएथीलीन की थिक्नेसीया कागज की मोटाई—

(क) $+25\%$ सह्यता सहित 100 गेज या 23.5 ग्राम/मी² से कम नहीं होगी; तथापि जब प्रयुक्त किया गया पॉलिएथीलीन 100 गेज या 23.5 ग्राम/मी² से अधिक हो तो न्यूनतम 100 गेज या 23.5 ग्राम/मी² के अधीन रहते हुए सह्यता $\pm 25\%$ होगी।

(ख) $+25\%$ की सह्यता सहित 300 गेज या 70.5 ग्राम/मी² से कम नहीं होगी तथापि जब प्रयुक्त किया गया पॉलिएथीलीन 300 गेज या 70.5 ग्राम/मी² से अधिक हो तो न्यूनतम 100 गेज या 23.5 ग्राम/मी² के अधीन रहते हुए सह्यता $\pm 25\%$ होगी।

(ग) $+20\%$ की सह्यता सहित 200 गेज या 47 ग्राम/मी² से कम नहीं होगी; तथापि जब प्रयुक्त किया गया पॉलिएथीलीन 200 गेज या 47 ग्राम/मी² से अधिक हो तो न्यूनतम 200 गेज या 47 ग्राम/मी² के अधीन रहते हुए सह्यता $\pm 20\%$ होगी।”

[सं० 6(18)/73 नि० नि० तथा नि० उ०]
सी० बी० कुक्रेती, संयुक्त निदेशक

ORDER

S.O. 2313.—Whereas the Central Government is of opinion that, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 4067, dated the 20th September, 1975 relating to quality control and inspection of Laminated Jute Products prior to their export in the manner specified below for the development of the export trade of India;

And whereas the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule II of Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

456 GI/78—2

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposal may forward the same within fortyfive days from the date of publication of the Order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, “World Trade Centre” (7th floor), 14/1B, Ezra Street, Calcutta-700001.

PROPOSALS

In clause 2 of the Annexure to the said order,—

(i) for sub-clause (3) the following shall be substituted namely:—

“Ends and picks per decimeter in the basic fabric shall be as stipulated in the export contract. A tolerance upto ± 7.0 per cent shall be permitted on the contractual specification in respect of ends and picks per decimeter.”

(ii) for sub-clause (4) the following shall be substituted; namely:—

“(4) The thickness of polythylene film or paper shall not be—

(a) less than 100 gauge or 23.5 gms/m² with a tolerance of $+25$ per cent so, however, when the polythylene use is more than 100 gauge or 23.5 gms/m² the tolerance shall be ± 25 per cent subject to a minimum of 100 gauge or 23.5 gms/m²;

(b) less than 300 gauge or 70.5 gms/m² with a tolerance of $+25$ per cent so, however, when the polythylene used is more than 300 gauge or 70.5 gms/m² the tolerance will be ± 25 per cent subject to a minimum of 300 gauge of 23.5 gms/m²;

(c) less than 200 gauge or 47 gms/m² with a tolerance of $+20$ per cent so, however, what the polythylene used is more than 200 gauge or 47 gms/m² the tolerance will be $+20$ per cent subject to a minimum of 200 gauge or 47 gms/m².”

[No. 6(18)/73-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

वाणिज्य मगरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1978

क्रा० प्रा० 2314.— सर्वश्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० राजीपुर, हरिद्वार (यू० पी०) को जापान से डीप होल बोरिंग एवं ट्रिपेन्डेन मशीन का आयात करने के लिए 40,00,797.00 रुपए 20,16,531.00 स्वीस क्रोनर्स (चालीस लाख सात सौ सतानवे रुपए मात्र) का एक आयात ला० सं० आई/सी जी/2069368/एस/एसडब्ल्यू/53/एच/41-42/सीजी-2 दिनांक 28-4-1975 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त ला० की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति बिल्कुल ही उपयोग में नहीं लार् गई है और उसमें बाकी बचे हुए 40,00,797.00 रुपए उपलब्ध थे।

2. अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने नोटरी, हरिद्वार के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं तदनुसार सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त ला० की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए, यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9(सीसी) के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० राजीपुर, हरिद्वार (यू० पी०) को जारी किए गए ला० सं० आई/सी/जी/2069368 दिनांक 28-4-1975 की उपर्युक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

3. उपर्युक्त ला० की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति लाइसेंस-धारी को भ्रम से जारी की जा रही है।

[संख्या सी जी-2/एन-1(76)/74-75/368]

टी० टी० ला, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1978

S.O. 2314.—M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., Ranipur, Hardwar (U.P.) were granted an import licence No. I/CG/2069368/S/SW/53/H/41-42/CG/II, dt. 28-4-75 for Rs. 40,00,797 Sw. Kr. 20,16,531 (Rupees Forty lakhs Seven hundred and Ninety Seven only) for import of One No. Deep Hole Boring and Trepanning Machine from Japan. They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes Copy of the said licence on the ground that the original Custom Purpose Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Custom Copy was utilised at all and the balance available on it was Rs. 40,00,797.

2. In support of this contention, the applicant has filed and affidavit duly sworn in before Notary Hardwar. I am accordingly satisfied that the original Custom Purpose Copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Custom copy of licence No. I/CG/2069368 dated 28-4-1975 issued to M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., Ranipur, Hardwar is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purpose Copy of the said licence is being issued separately to the licence.

[No. CG-II/H. I(76)/74-75/258]

T. T. LA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 1978

का० घा० 2315.—सर्वोत्ती तेल एवं प्राकृतिक गैस आयुक्त, तेल भवन, देहरादून का अनुमेष फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस संख्या घाई/ए/1404298, दिनांक 21-9-74 प्रदान किया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयुक्त ने सूचना दी है कि लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है।

2. अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है, अधोदस्ताधरी सन्तुष्ट है कि लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि लाइसेंस की उपर्युक्त सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए।

3. लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द कर दी गई है और उसकी एक अनुलिपि प्रति भ्रम से जारी की जा रही है।

[संख्या-एन० सी०/215/74-75/पीएलएस/बी/268]

यू० एस० रावत, उप-मुख्य नियंत्रक,

कृते मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 7th June, 1978

S.O. 2315.—M/s. Oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan, Dehradun was granted Licence No. I/A/1404298 dated 21-9-74 for the import of permissible spare parts. The ONGC has reported that the customs copy of the licence has been lost/misplaced and has requested to issue duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit, the undersigned is satisfied that the customs copy of the licence has been lost and directs that the duplicate copy of the said customs purpose copy of the licence be issued.

The original customs purpose copy of the licence has been cancelled, and a duplicate copy of the same is being issued separately.

[File No. ND/215/74-75/PLS/B/268]

U. S. RAWAT, Dy. Chief Controller,
for Chief Controller

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक—आयात तथा निर्यात का कार्यालय, मद्रास)

आदेश

मद्रास, 8 जून, 1978

का० घा० 2316.—सर्वोत्ती रहमान्या स्टोर्स, वाणिगवैश्य गली, तेनकरे, वेरियकुलम पि० ओ०, मयुरे जिल्ला को, अप्रैल-मार्च 1977-78 की अवधि के लिए, रुपये 5 हजार तक कच्चा गरी का तेल का आयात करने के लिए लाइसेंस सं० पि-अट-1930337 दिनांक 26-12-77 जारी किया गया था। लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए इसलिए प्रार्थना की है कि वही प्रति, किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कर लिये बिना और उसका उपयोग किये बिना खो गयी है अथवा अस्थान में रख दी गयी है। आवेदक ने अपने बिवाद के समर्थन में एक शपथपत्र भी पेश किया है।

मैं सन्तुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या पि-अट-1930337 दिनांक 26-12-77 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ की मूल प्रति खो गयी है अथवा अस्थान में रख दी गयी है और मैं आज्ञा देता हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की दूसरी प्रति जारी किया जाय। लाइसेंस संख्या पि-अट-1930337 दिनांक 26-12-77 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ की मूल प्रति एतद्वारा रद्द किया जाता है।

[सं० ऐटिसी-2204-ब-घाईल्स-एएस-79/एयू]

एस० नरसिम्हान, उप-मुख्य नियंत्रक,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Madras)

ORDER

Madras, the 8th June, 1978

S.O. 2316.—M/s. Rahumanja Stores, Vanigavysia Street, Thenkarai, Periakulam P.O., Madurai Dist. was issued with an import licence No. P/S/1930337 dated 26-12-77 for Rs. 5 lakhs for the import of Raw Palmoil for the period A.M./77-78. The licensee has since applied for a duplicate copy of the above licence for Customs Purposes Copy only since the same has been lost/misplaced without having been registered with any Customs Authority and utilised it at all. In support of their contention the applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that the original Customs Purposes Copy of the import licence No. P/Z/1930337 dated 26-12-77 has been lost/misplaced and direct that a duplicate Customs Purposes copy of the above licence shall be issued to the applicant. The original Customs Purposes copy of the licence P/Z/1930337 dated 26-12-77 is hereby cancelled.

[No. ITC/2205/E. oils/AM. 78/AU]

S. NARASIMHAN, Dy. Chief Controller.
for Jt. Chief Controller

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1978

का० घा० 2317.—जयदेव इन्स्टिट्यूट आफ काबियोलांजी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल/बंगलौर मेडिकल कालेज सिटी मार्केट एरिया, बंगलौर-560002 की संलग्न सूची के अनुसार मल्टिपैनल आप्टिकल फोटोग्राफिक रिकार्डर

डी०आर०-12 के आयात के लिये केवल 1,30,161/- रुपये का आयात लाइसेंस संख्या-जी०/ए०/1074243/सी०/एक्स०एक्स०/62/एच०/43-44/आई०एल०एस०, दिनांक 15-1-1977 प्रदान किया गया था। उन्होंने आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं की और प्रयुक्त नहीं हुई की। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस संख्या जी०/ए०/1074243, दिनांक 15-1-1977 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूँ कि एक अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जाए। आयात लाइसेंस संख्या-जी०/ए०/1074243 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या जे० 5-7/मैड/76-77/आई०एल०एस०/381]

सी०एस० आर्य, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi)
ORDER

New Delhi, the 31st July, 1978

S.O. 2317.—Jayadeva Institute of Cardiology, Govt. Victoria Hospital/Bangalore Medical College City Market Area, Bangalore-560002 was granted import licence No. G/A/1074243/C/xx[62]H[43-44]ILS dated 15-1-1977 for Rs. 1,30,161 only for the import of multichannel optical photographic recorder DR.12 as per list attached. They have applied for a duplicate copy for Customs purposes of the import licence on the ground that the original Customs purposes copy of the import licence has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes copy of the licence was not registered with any Customs House and not utilised. In support of this contention, they have filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes copy of import licence No. G/A/1074243 dated 15-1-1977 has been lost/misplaced and direct that a duplicate Customs Purposes copy should be issued. The original Customs Purposes copy of import licence No. G/A/1074243 is cancelled.

[No. J. 5-7/Med/76-77/ILS/38]

C. S. ARYA, Dy. Chief Controller

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 1978-07-27

क्र० आ० 2318 :—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विज्ञान) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है/हैं और यह/ये फीस प्रत्येक वस्तु के आगे दी गई तिथि (यों) से लागू होंगी।

अनुसूची

संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए कार्बन इस्पात की डली वस्तुएं	IS : 1030—1974 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए कार्बन इस्पात की डली वस्तुओं की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 2.00	1978-04-01
2.	जल, गैस और मल निकास के लिए ऐस्बेस्टास सीमेंट दाब पाइपों के साथ लगने वाले डलवां लोहे के स्पेशल	IS : 5531 (भाग 1 से 3)—1977 जल, गैस और मल निकास के लिए ऐस्बेस्टास सीमेंट दाब पाइपों के साथ लगने वाले डलवां लोहे के स्पेशल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	(1) पहली 500 इकाइयों के लिए रु० 5.00 प्रति इकाई और (2) 501वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए रु० 3.00 प्रति इकाई	1978-04-16
3.	ठंडे संरक्षण और फ्लेज देने के कार्यों के लिए गर्म बेकलित इस्पात की पट्टी और फ्लैट	IS : 5986—1970 ठंडे संरक्षण और फ्लेज देने के कार्यों के लिए गर्म बेकलित इस्पात की पट्टी और फ्लैट की विशिष्टि	एक मीटरी टन	30 पैसे	1977-11-01

[सं० सी एस डी/13 : 10]

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 1978-07-27

S.O. 2318 :—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Carbon steel castings for general engineering purposes	IS: 1030—1974 Specification for carbon steel castings for general engineering purposes (second revision)	One Tonne	Rs. 2.00	1978-04-01
2.	Cast iron specials for use with asbestos cement pressure pipes for water, gas and sewage.	IS: 5531 (Parts I to III)—1977 specification for cast iron specials for use with asbestos cement pressure pipes for water, gas and sewage. (first revision)	One Tonne	(i) Rs. 5.00 per unit for the first 500 units and (ii) Rs. 3.00 per unit for the 501st unit and above.	1978-04-16
3.	Hot-rolled steel plates and flats for cold-forming and flanging operations.	IS : 5986—1970 Specification for hot-rolled steel plates and flats for cold-forming and flanging operations.	One Tonne	30 Paise	1977-11-01

[No. CMD/13 : 10]

क्रा० आ० 2319 :—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विभाग) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए व्योरे के अनुसार निर्धारित की गई है/हैं और यह/ये फीस 1978-01-16 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सतह कठोरीकरण के लिए कार्बन इस्पात की ठली वस्तुएं	IS : 2707—1973 सतह कठोरीकरण के लिए कार्बन इस्पात की ठली वस्तुओं की विधि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	₹ 2.00
2.	1.5 प्रतिशत मैंगनीज इस्पात की ठली वस्तुएं	IS : 2708—1973 1.5 प्रतिशत मैंगनीज युक्त इस्पात की ठली वस्तुओं की विधि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	₹ 2.00

[संख्या सीएमडी/13 : 10]

वाई० एस० वेंकटेश्वरन, अपर महानिदेशक

S.O. 2319.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from 1978-01-16.

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Carbon steel castings for surface hardening	IS : 2707—1973 Specification for carbon steel casting for surface hardening (first revision).	One Tonne	Rs. 2.00
2.	1.5 per cent manganese steel castings	IS : 2708—1973 Specification for 1.5 per cent manganese steel castings (first revision)	One Tonne	Rs. 2.00

[No. CMD/B:10]


Y. S. VENKATESWARAN, Addl. Director General

नई दिल्ली, 1978-07-31

का०प्रा० 2320.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) 1955 के नियम 4 के उपबिनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किए हैं जिसकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानक के शीर्षक सहित अनुसूची में दिए गए हैं :—

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिह्न 1978-02-16 से लागू होंगे :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की सं० और एकाई	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1		फॉसालोन धूलन पाउडर	IS : 8489-1977 फॉसालोन धूलन पाउडर की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिनमें 'ISI' शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई गैसी और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसूचना दी गई है।

[सं० सी एम डी/13:9]


वाई० एस० वेंकटेश्वरन, धवर महाविदेशक

New Delhi, the 1978-07-31

S.O. 2320.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1978-02-16 :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Phosalone dusting powder	IS : 8489-1977 Specification for phosalone dusting powders	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in col. (2); the number of the Indian Standard being super-scribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9]

Y. S. VENKATESVARAN, Addl. Director General

उद्योग मन्त्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1978

का०प्रा० 2321.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की देखरेख) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा, 3 द्वारा प्रवक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है अधिसूचना सं० का०प्रा० 1323, तारीख 23 मार्च, 1976 के अनुसार सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री सी० सुब्रमणियम के स्थान पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे निवेश करती है कि पूर्वोक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ

(2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का नाम	सरकारी स्थान
1	2
श्री वाता राम, धवर सचिव, उद्योग मन्त्रालय, औद्योगिक विकास विभाग	उद्योग भवन

[का० सं० डी-11012/12/73-जी०ए०]

बी०आर०आर० अय्यंगर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 28th July, 1978

S.O. 2321.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column (1) of the Table below, being Gazetted Officer of Government to be Estate Officer for the purpose of the said Act, vice Shri C. N. Subramanian, appointed as Estate Officer vide Notification S. O. 1323 dated 23rd March, 1976 and further directs that the aforesaid officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

name of Officer	Public Premises
1	2
Shri Data Ram, Under Secretary, Ministry of Industry, Department of Industrial Development	Ydyog Bhavan

[F. No. D-11012/12/73-G.A.]
B. R. R. IYENGAR, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1978

क्र०प्र० 2322.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना क्र०प्र० सं० 1600, तारीख 8 मई, 1976 द्वारा, इससे उपा-बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में 5900.00 एकड़ (लगभग) या 2387.61 हेक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के आ-प्राप्त की सूचना दी थी ;

[और उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, धारा 7 की उक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 मई, 1978 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और कालावधि को उक्त कालावधि के रूप में विनि-विष्ट करती है, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि अर्जित करने या ऐसी भूमि में या पर कोई अधिकार अर्जित करने के अपने प्राप्ति की सूचना दे सकती है ।

अनुसूची

दुधिबुवा ब्लॉक-1

(सिंगरौली कोयला क्षेत्र)

मध्य प्रदेश

रेखांक सं० राजस्व/66/75

तारीख 21-11-75

(इसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित की गई है)

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील परगना सं०	जिला	क्षेत्रफल टिप्पण
1	2	3	4	5	6
1.	करवारी	सिंगरौली	50	सिंगरौली	सिधौ पूर्ण
2.	चुरिडाह	"	179	"	" भाग

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	दुधिबुवा	सिंगरौली	249	सिंगरौली	"	"	पूर्ण
4.	मातोली	"	446	"	"	"	भाग

कुल क्षेत्रफल 5900.00 एकड़ (लगभग)

या 2387.61 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क—ख

रेखा पिजरेह की ग्राम सीमा से प्रारम्भ होती है तथा मातोली ग्राम से होकर जाती है (जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग भी है) और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख—ग

रेखा मातोली और दुधिबुवा ग्रामों की सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है (जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग भी है) और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग—घ

रेखा मातोली ग्राम से होकर जाती है [जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग भी है] और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ—ङ—च

रेखा मातोली ग्राम से होकर, दुधिबुवा और सरसोबा राजादोला ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है [जो कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित जयन्त ब्लॉक की सामान्य सीमा का भाग भी है तथा कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 4(1) के अधीन अर्जित जयन्त, ब्लॉक विस्तारण की सामान्य सीमा का भाग भी है] और बिन्दु "च" पर मिलती है ।

च—छ

रेखा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है (जो मध्य प्रदेश के दुधिबुवा ग्राम के साथ और उत्तर प्रदेश के विस्फावर, खरिया और भेरवा ग्रामों के साथ सामान्य सीमा का भाग भी है) और बिन्दु "छ" पर मिलती है ।

छ—ज

रेखा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है [जो दुधिबुवा ग्राम के साथ सामान्य सीमा का भाग और मध्य प्रदेश के चुरि-डाह ग्राम के साथ उत्तर प्रदेश के जामतिला, बंसी ग्रामों तथा ककरी ग्राम के भाग के साथ सामान्य सीमा भी बनाती है, जो कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित जोरीबोरा ब्लॉक की सामान्य सीमा का भाग भी है] और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।

ज—क रेखा चुरिवाह ग्राम से होकर, कोरवारी और सिगुर्दा, कोरवारी और चटका, मातौली और चटका ग्रामों की सामान्य सीमा तथा मातौली और पिजरेह की सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19/10/76-सी० एल० (I)]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 25th July, 1978

S. O. 2322—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1600—dated the 8th May, 1976, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 5900.00 acres (approximately) or 2387.61 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended hereto ;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 8th May, 1978, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

THE SCHEDULE

Dudhi chuwa Block-1

(Singrauli Coalfield)

Madhya Pradesh

Drg. No. Rev/66/75
dated 21-11-75

(showing lands notified for prospecting)

Sl. Village No.	Tahsil	Tahsil No.	Pargana	District	Area	Remarks
1. Karwari	Singrauli	50	Singrauli	Sidhi		Full
2. Churidah	"	179	"	"		Part
3. Dudhi-chuwa	"	249	"	"		Full
4. Matouli	"	446	"	"		Part

Total area : 5900.00 acres (approximately)
or 2387.61 hectares (approximately)

Boundary description :

A—B line starts from village Boundary of Pijreh, then passes through village Matouli [which also forms the part common boundary of area acquired u/s 17(1) of Mines and Minerals (R& D) Act, 1957] and meets at point 'B'.

B—C lines passes along the part common boundary of villages Matouli & Dudhichuwa [which also forms the part common boundary of area acquired u/s 17 (1) of Mines and Minerals (R&D) Act, 1957] and meets at point 'C'.

C—D line passes through village Matouli [which also forms the part common boundary of the area acquired u/s 17 (1) of Mines & Minerals (R&D) Act, 1957] and meets at point 'D'.

D—E—F—lines pass through village Matouli, along the common boundary of villages Dudhichuwa & Sarsoba Raja Tola [which also forms the part common boundary of Jayant Block acquired u/s 9(1) of C. B. A. (A&D) Act, 1957 and part common boundary of Jayant Block Extn. notified u/s 4(1) of C. B. A. Act, 1957] and meet at point 'F'.

F—G line passes along the part common boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh (which also forms common boundary with the village Dudhichuwa of Madhya Pradesh and with the villages Chilkadanr, Kharia & Bhairwa of Uttar Pradesh) and meets at point 'G'.

G—H line passes along the part common boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh [which also forms part common boundary with the village Dudhichuwa & common boundary with the village Churidah of Madhya Pradesh and with the villages Jamsila, Bansi and part village of Kakri of Uttar Pradesh, which also forms part common boundary of Jogichawra Block acquired u/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957] and meets at point 'H'.

H—A line passes through village Churidah ; along the common boundary of villages Korwari and Jhingurda, Korwari & Chatka, Matouli & Chatka and part common boundary of Matouli & Pijreh and meets at starting point 'A'.

[No. 19 (10)/76- CL (i)]

क्रा० प्रा० 2323.—केन्द्रीय सरकार, ने कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०प्रा० 1546, तारीख 1 मई, 1976 द्वारा, इससे उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में 3500.00 एकड़ (लगभग) या 1416.38 हेक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, धारा 7 की उक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 1978 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और कालावधि की उस कालावधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि अर्जित करने या ऐसी भूमि में या पर कोई अधिकार अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है।

अनुसूची

दुधिचुवा ब्लॉक-2

मिगरोली कोयला क्षेत्र

(उत्तर प्रदेश)

रेखांक सं० राजस्व/66क/75

तारीख 21-11-75

(इसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाई गई है)

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील सीस सं०	थाना	परगना	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	परसाबाज राजा	दुधी	34	मिसरा	सिंग-मिरजा-			
				(खैरवा)	रोली पुर			
2.	जोगीचौरा	"	46	"	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	चिलकावार	दुधी	49	मिसरा	सिंगरौली	मिरजापुर	भाग	
4.	कोटा	"	82	"	"	"	"	
5.	खरिया	"	115	"	"	"	"	
6.	भैरवा	"	—	"	"	"	"	

कुल क्षेत्रफल 3500.00 एकड़ (लगभग)
या 1416.38 हेक्टेयर्स (लगभग)

सीमा वर्णन :

- अ-अ रेखा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है (जो उत्तर प्रदेश के चिलकावार ग्राम के साथ तथा मध्य प्रदेश के सरसोबा राजा टोला, सरसोबा लाल टोला ग्रामों के साथ और चन्देली ग्राम के भाग के साथ सामान्य सीमा का भी भाग है) और बिन्दु "अ" पर मिलती है।
- अ-अ रेखा चिलकावार, कोटा, खरिया और परसावार राजा ग्रामों से होकर जाती है और "अ" बिन्दु पर मिलती है।
- अ-ड रेखा परसावार राजा, जोगीचौरा और भैरवा ग्राम से होकर जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है।
- ड-छ रेखा भैरवा और जमसिला ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है (जो कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित जोगीचौरा ब्लॉक की सामान्य सीमा का भाग भी है) और बिन्दु "छ" पर मिलती है।
- छ-ज रेखा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सामान्य सीमा के भाग के साथ साथ जाती है (जो उत्तर प्रदेश के भैरवा, खरिया और चिलकादार ग्रामों के साथ तथा मध्य प्रदेश के दुधिचुवा ग्राम के साथ सामान्य सीमा भी है) और आरम्भिक बिन्दु "ज" पर मिलती है।

[सं० 19(10)/76-सी०एल०(ii)]

एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

S.O.2323.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1546 dated the 1st May, 1976, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 3500.00 acres (approximately) or 1416.38 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended hereto ;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 1st May, 1978, as the period within the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

Dudhichuwa Block-II
Singrauli Coalfield

(Uttar Pradesh)

Drg. No. Rev/66A/75

Dated 21-11-75

(showing lands notified for prospecting)

Sl. village No.	Tahsil	Tahsil No.	Thana	Par-gana	Distt.	Area remarks
1. Parsa-war Raja	Dudhi	34	Misra (Kair-wa)	Sing-rauli	Mirza-pur	Par.
2. Jogi-chowra	"	46	"	"	"	"
3. Chilka-danr	"	49	"	"	"	"
4. Kota	"	82	"	"	"	"
5. Kharia	"	115	"	"	"	"
6. Bhairwa	"	—	"	"	"	"

Total area : 3500.00 acres
(approximately)
or
1416.38 hectares
(approximately)

Boundary description :

F—I line passes along the part common boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh (which also forms part common boundary with the village Chilkadanr of Uttar Pradesh and with the villages Sarsoba Raja Tola Sarsoba Lal tola and part of village Chadel of Madhya Pradesh) and meets at point 'I'.

I—J line passes through villages Chilkadanr, Kota, Kharia and Parsawar Raja and meets at point 'J'.

J—K line passes through village Parsawar Raja, Jogichowra and Bhairwa and meets at point 'K'.

K—G line passes along the part common boundary of villages Bhairwa and Jamsila (which also forms part common boundary of Jogichowra Block acquired u/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 and meets at point 'G'.

G—F line passes along the part common boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh (which also forms common boundary with the villages of Bhairwa, Kharia and Chilkadanr of Uttar Pradesh and with the village of Dudhichuwa of Madhya Pradesh) and meets at starting point 'F'.

[No. 19(10)/76-CL (ii)]

S. R. A. RIZVI, Director.

(बिद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1978

का०आ० 2324.—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 को उपधारा (5) के अनुसरण में, ब्यास परियोजना यूनिट-1 (ब्यास सतलुज लिंक परियोजना) के निम्नलिखित संघटकों को, जिनके सम्बन्ध में सन्निर्माण पूरा हो गया है उक्त अधिनियम

की धारा 80 की उपधारा (6) के साथपठित धारा 79 के अधीन गठित भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को, 1 सितम्बर, 1978 से अन्तर्गत करती है, अर्थात् :—

- (क) पंडोह बांध और उससे अनुलग्न वर्क्स जिनमें पंडोह जलाशय, उमड़ भाग और हट्टेक संरचना सम्मिलित हैं।
- (ख) पंडोह-बग्गो सुरंग जिसमें सामला एडिट, बग्गो नियन्त्रण वर्क्स और बग्गो उपमार्ग सम्मिलित हैं।
- (ग) सुन्दरनगर जल-विद्युत चैनल और उससे अनुलग्न वर्क्स जिनमें इत्युक्त टेल नियन्त्रण संरचना सम्मिलित हैं।
- (घ) संतुलक जलाशय और उससे अनुलग्न वर्क्स।
- (ङ) सुन्दरनगर-सतलुज सुरंग जिसमें पुंग हट्टेक वर्क्स और हराबागे एडिट सम्मिलित हैं।
- (च) उपमार्ग सुरंग, जिसमें गेट चेम्बर और उपमार्ग बूट सम्मिलित हैं।

[सं० 21/24/77-बो०एण्ड बो०/डो० III]

पी० एम० बलिभप्पा, संयुक्त सचिव

(Department of Power)

New Delhi, the 28th July, 1978

S.O. 2324.—In pursuance of sub-section (5) of section 80 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby transfers, with effect from 1st September, 1978 the following components of the Beas Project Unit-I (Beas Sutlej Link Project) in relation to which the construction has been completed, to the Bhakra Beas Management Board constituted under section 79, read with sub-section (6) of section 80, of the said act namely :—
I-DAM :

- (a) Pandoh Dam and works appurtenant thereto including Pandoh Reservoir, spillway and intake structure.
- (b) Pandoh-Baggi Tunnel including Samla adit, Baggi control works and Baggi by-pass.
- (c) Sundernagar Hydel Channel and works appurtenant thereto including gated tail control structure.
- (d) Balancing Reservoir and works appurtenant thereto.
- (e) Sundernagar Sutlej Tunnel including Pung intake works and Harabagh adit.
- (f) By-pass tunnel including gate chamber and by-pass chute.

[No. 21/24/77-B&B/D. III]

P. M. BELLIPPA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1978

का०आ० 2325.—सरकारी स्थान (अप्रामाणिक अधिभोगियों की बेव-खली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त

पर्यटन और नगर विमान नमंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1978

आदेश

का० आ० 2326.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम 1965 के नियम 8 के उपनियम (2) नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2395 तारीख 21 जुलाई 1972 को अधिकांत करते हुए आदेश करते हैं कि :—

- (1) नीचे दी गयी अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ज में के पदों की बाबत स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधि-कारी होंगे— और

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो भारतीय खाद्य निगम, एक निगमित प्राधिकरण का एक अधिकारी है और जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति में समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त निगम के या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए या उसके द्वारा या उसके निमित्त अधिगृहीत परिसरों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधि-कारिता की स्थानीय सीमाएं
उपमण्डलीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, मुम्बई।	मुम्बई में भारतीय खाद्य निगम के या उसके पट्टे पर लिए गए या उसके द्वारा या उसके निमित्त अधिगृहीत परिसर।

[सं० 27(2)/77-एफ०सी० II]

के० सी० एस० आचार्य, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

New Delhi, 26th July, 1978.

S.O.2325—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer of the Food Corporation of India, a corporate authority, and being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Government of India, to be an estate officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction, specified in column (2) of the said Table, in respect of the premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the said Corporation.

TABLE

Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
Deputy Zonal Manager, Food Corporation of India, Bombay	Premises belonging to , or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the Food Corporation of India in Bombay.

[No. 27(2)/77-F.C. II].

K.C.S. ACHARYA, Jt. Secy.

- (2) उक्त अनुसूची के भाग 2 और 3 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग और साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख के पदों की बाबत स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के सम्बन्ध में स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और स्तंभ (3) और (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

भाग-1—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'

पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्त्रियाँ अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और ऐसी शास्त्रियाँ जो वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम II में की गयी संख्याओं के प्रतिनिर्देश से)	अपील प्राधिकारी	
(1)	(2)	प्राधिकारी	शास्त्रियाँ	(5)
नागर विमानन विभाग केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आणुलिपिक सेवा में सम्मिलित पदों से भिन्न सभी पद	महानिदेशक, नागर विमानन	महानिदेशक, नागर विमानन उपमहानिदेशक, नागर विमानन	सभी (i) से (iv) तक *	

भाग 2—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'

नागर विमानन विभाग (मुख्यालय कार्यालय)	निदेशक, प्रशासन	निदेशक, प्रशासन	सभी	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आणुलिपिक सेवा में सम्मिलित पदों से भिन्न सभी पद				
इस स्तंभ में निम्न प्रविष्टि (ii) से (vi) तक में विनिर्दिष्ट अधीनस्थ कार्यालयों से भिन्न प्रादेशिक और अन्य अधीनस्थ कार्यालय				
(i) अधीक्षक/प्रधान लिपिक/हवाई क्षेत्र सहायक/संचार सहायक/तकनीकी सहायक/ज्येष्ठ अतिरिक्त फोरमैन/वार्जमैन	प्रशासन निदेशक	प्रशासन निदेशक सम्बद्ध प्रादेशिक निदेशक	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
अन्य पद	सम्बद्ध प्रादेशिक निदेशक	सम्बद्ध प्रादेशिक निदेशक	सभी	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
(ii) रेडियो सन्निर्माण और विकास एकक				
अधीक्षक/प्रधान लिपिक/संचार सहायक/तकनीकी सहायक	प्रशासन निदेशक	प्रशासन निदेशक सम्बद्ध प्रादेशिक निदेशक	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
ज्येष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक और अन्य लिपिकीय पद	प्रादेशिक निदेशक	प्रादेशिक निदेशक निदेशक, रेडियो सन्निर्माण और विकास एकक	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
अन्य पद	निदेशक, रेडियो सन्निर्माण और विकास एकक	निदेशक, रेडियो सन्निर्माण और विकास एकक		
(iii) कार्यालय निदेशक, वायुयान निरीक्षण, कानपुर				
सभी पद	प्रादेशिक निदेशक	प्रादेशिक निदेशक निदेशक, वायुयान निरीक्षण	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
(iv) कार्यालय प्रधान, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, बलाहाबाद				

1	2	3	4	5
अधीक्षक/प्रधान लिपिक/संचार सहायक/ हवाई क्षेत्र सहायक/तकनीकी सहायक	प्रशासन निदेशक	प्रशासन निदेशक प्रधान, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
अन्य पद	प्रादेशिक निदेशक	प्रादेशिक निदेशक प्रधान, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
(v) कार्यालय, नियंत्रक केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो, नई दिल्ली				
अधीक्षक/प्रधान लिपिक/संचार सहायक/ तकनीकी सहायक	प्रशासन निदेशक	प्रशासन निदेशक नियंत्रक, केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
अन्य पद	प्रादेशिक निदेशक	प्रादेशिक निदेशक नियंत्रक, केन्द्रीय रेडियो सामग्री डिपो	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
(vi) कार्यालय, उपनिदेशक उपस्कर, नई दिल्ली				
अधीक्षक/प्रधान लिपिक/राजमैन/हवाई क्षेत्र सहायक/तकनीकी सहायक	प्रशासन निदेशक	प्रशासन निदेशक उपनिदेशक, उपस्कर	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन
अन्य पद	प्रादेशिक निदेशक	प्रादेशिक निदेशक उपनिदेशक, उपस्कर	सभी (i) से (iv) तक	उपमहानिदेशक, नागर विमानन

भाग III—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'

नागर विमानन विभाग (मुख्यालय कार्यालय)

सभी पद प्रवेश और उपकार्यालय	सहायक प्रशासन निदेशक	सहायक प्रशासन निदेशक	सभी	प्रशासन निदेशक
प्रादेशिक निदेशक का कार्यालय और भराजपत्रित अधिकारियों के प्रभारा- धीन अन्य उपकार्यालय				
सभी पद	प्रशासन अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	सभी	प्रादेशिक निदेशक
राजपत्रित अधिकारियों के प्रभाराधीन हवाई क्षेत्र अधिकारी				
सभी पद	ज्येष्ठ हवाई क्षेत्र अधिकारी या हवाई क्षेत्र अधिकारी या सहायक हवाई क्षेत्र अधि- कारी या सहायक संचार अधिकारी या सहायक तक- नीकी अधिकारी संबद्ध	ज्येष्ठ हवाई क्षेत्र अधिकारी या हवाई क्षेत्र अधिकारी या सहायक हवाई क्षेत्र अधिकारी या सहायक संचार अधिकारी या सहायक तकनीकी अधिकारी संबद्ध	सभी	प्रादेशिक निदेशक
उपनिदेशक उपस्कर का कार्यालय				
सभी पद	उपनिदेशक, उपस्कर	उपनिदेशक उपस्कर	सभी	प्रादेशिक निदेशक
नियंत्रक, केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो				
सभी पद	ज्येष्ठ संचार अधिकारी	ज्येष्ठ संचार अधिकारी	सभी	प्रादेशिक निदेशक
रेडियो संश्लिष्ट और विकास एकक				
सभी पद	ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी	ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी	सभी	निदेशक रेडियो संश्लिष्ट और विकास एकक
राजपत्रित अधिकारियों के प्रभाराधीन संचार केन्द्र				
सभी पद	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	सभी	प्रादेशिक निदेशक

1	2	3	4	5
ज्येष्ठ वायुयान निरीक्षक, या वायुयान निरीक्षक के प्रभारधीन अधीनस्थ वैमानिक निरीक्षण कार्यालय				
सभी पद	ज्येष्ठ वायुयान निरीक्षक या वायुयान निरीक्षक	ज्येष्ठ वायुयान निरीक्षक या वायुयान निरीक्षक	सभी	प्रादेशिक निरीक्षक
ग्लाइडिंग केन्द्र				
सभी पद	प्रभारी-अनुदेशक	प्रभारी-अनुदेशक	सभी	प्रादेशिक निदेशक
कार्यालय, प्रधान, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद				
सभी पद	प्रशासन अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	सभी	प्रादेशिक निदेशक
कार्यालय निदेशक, वायुयान निरीक्षण, कानपुर				
सभी पद	ज्येष्ठ वायुयान निरीक्षक	ज्येष्ठ वायुयान निरीक्षक	सभी	निदेशक वायुयान निरीक्षक

टिप्पण:—(1) यदि इस अनुसूची के स्तंभ (i) में विनिर्दिष्ट किसी कर्मचारी को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उच्च पंक्ति के किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो तो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के खंड (v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति प्रथम उल्लिखित प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा उस कर्मचारी पर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) निम्नलिखित अधिकारी अर्थात् (1) निदेशक रेडियो सश्रमार्ण और विकास एकक, (2) निदेशक, वायुयान निरीक्षण, (3) प्रधानाचार्य, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, (4) नियंत्रक केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो और (5) उपनिदेशक, उपस्कर, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के प्रयोजनार्थ प्रादेशिक निदेशक दिल्ली प्रदेश की अधिकारिता में आएंगे, जो अपने निहित अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग उक्त कार्यालयों के कर्मचारिकृन्द की बाबत करेंगे।

[सं० सी० 11011/2/76-ईएच (4915-बी-ई/77)]

एए० एकाम्बरम, उप-सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

ORDER

New Delhi, the 20th July, 1978

S.O. 2326,—In exercise of the power conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and appeal) Rules 1965, and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Tourism and Civil Aviation, No. S.O. 2395, dated the 21st July, 1972 the President hereby order that :

(1) in respect of the posts in the General Central Service Group B, specified in column (1) of Part I of the Schedule given below, the authority specified in column (2) shall be the Appointing Authority and the authorities specified in column (3) shall be the Disciplinary Authorities in regard to the penalties specified in column (4) ; and

(2) in respect of the posts in the General Central Service, Group C and the General Central Service, Group D, specified in column (1) of Parts II and III of the said Schedule, the authority specified in column (2) shall be the Appointing Authority and the authorities specified in columns (3) and (5) shall be the Disciplinary Authorities and the Appellate Authority respectively in regard to the penalties specified in column (4).

SCHEDULE

Part I—General Central Services Group 'B'

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11).	
		Authority	Penalties
1	2	3	4
Civil Aviation Department.			
All posts other than those included in Central Secretariat Service and Central Secretariat Stenographers' Services.	Director General of Civil Aviation	Director General of Civil Aviation	All
		Deputy Director General of Civil Aviation.	(i) to (iv)

1	2	3	4	5
Part II—General Central Services Group 'C'				
Civil Aviation Department (Headquarters Office)				
All posts other than those included in Central Secretariat Clerical Service and Central Secretariat Stenographers' Service.	Director of Administration	Director of Administration	All	Deputy Director General of Civil Aviation.
Regional and other subordinate offices other than the subordinate offices specified in this column in entries (ii) to (iv) below :				
(i) Superintendent/Head Clerk/Aerodrome Assistant/Communication Assistant/Technical Assistant/Senior Fire Foreman/Chargeman.	Director of Administration	Director of Administration Regional Director concerned	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation.
Other posts	Regional Director concerned	Regional Director concerned	All	Deputy Director General of Civil Aviation.
(ii) Radio Construction and Development Unit				
Superintendent/Head Clerk/Communication Assistant/Technical Assistant.	Director of Administration	Director of Administration Regional Director concerned	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation.
Senior Clerk/Junior Clerk and other Ministerial posts	Regional Director	Regional Director Director, Radio Construction and Development Unit.	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation
Other posts.	Director, Radio Construction and Development Unit.	Director, Radio Construction and Development Unit.	All	
(iii) Office of the Director, Aircraft Inspection, Kanpur				
All posts	Regional Director.	Regional Director. Director, Aircraft Inspection.	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation.
(iv) Office of the Principal, Civil Aviation Training Centre, Allahabad.				
Superintendent/Head Clerk/Communication Assistant/Aerodrome Assistant/Technical Assistant.	Director of Administration	Director of Administration Principal, Civil Aviation Training Centre, Allahabad.	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation.
Other posts	Regional Director	Regional Director Principal, Civil Aviation Training Centre, Allahabad	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation
(v) Office of the Controller, Central Radio Stores, Depot, New Delhi.				
Superintendent/Head Clerk/Communication Assistant/Technical Assistant.	Director of Administration	Director of Administration Controller, Central Radio Stores Depot.	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation.
Other posts	Regional Director	Regional Director. Controller, Central Radio Stores Depot.	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation
(vi) Office of the Deputy Director of Equipment, New Delhi.				
Superintendent/Head Clerk/Chargeman/Aerodrome Assistant/Technical Assistant	Director of Administration	Director of Administration Deputy Director of Equipment.	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation.
Other posts	Regional Director.	Regional Director. Deputy Director of Equipment.	All (i) to (iv)	Deputy Director General of Civil Aviation.

1	2	3	4	5
Part III—General Central Services Group 'D'				
Civil Aviation Department (headquarters office)				
All posts	Assistant Director of Administration	Assistant Director of Administration	All	Director of Administration.
Regions and Sub-offices.				
Office of the Regional Director and other Sub-Offices Under the charge of non-gazetted Officers*				
All posts	Administrative Officer	Administrative Officer	All	Regional Director
Aerodrome Offices in charge of Gazetted Officers				
All posts	Senior Aerodrome Officer of Aerodrome Officer or Assistant Aerodrome Officer or Assistant Communication Officer or Assistant Technical Officer concerned.	Senior Aerodrome Officer or Aerodrome Officer or Assistant Aerodrome Officer or Assistant Communication Officer or Assistant Technical Officer, concerned.	All	Regional Director
Office of the Deputy Director of Equipment				
All Post	Deputy Director of Equipment.	Deputy Director of Equipment.	All	Regional Director
Office of the Controller Central Radio Stores Depot.				
All posts	Senior Communication Officer	Senior Communication Officer	All	Regional Director
Radio Construction and Development Unit				
All posts	Senior Technical Officer	Senior Technical Officer	All	Director Radio Construction and Development Unit.
Communication stations in charge of Gazetted Officer				
All posts	Officer-in-Charge	Officer-in-charge	All	Regional Director
Subordinate Aeronautical Inspection Offices under the charge of Senior Aircraft Inspector or an Aircraft Inspector.				
All posts	Senior Aircraft Inspector or Aircraft Inspector.	Senior Aircraft Inspector or Aircraft Inspector	All	Regional Director
Gliding Centre				
All posts	Instructor-in-Charge	Instructor-in-Charge	All	Regional Director
Office of the Principal Civil Aviation Training Center, Allahabad.				
All posts	Administrative Officer	Administrative Officer	All	Regional Director
Office of the Director, Aircraft Inspection, Kanpur				
All posts	Senior Aircraft Inspector	Senior Aircraft Inspector	All	Director Aircraft Inspection.

NOTE : (1) In case an employee specified in column (1) of this Schedule has been appointed prior to the publication of this Order in the Official Gazette by an authority higher in rank to the authority specified in column 2, then no penalty specified in clauses (v) to (ix) rule 11 of the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 shall be imposed upon that employee by any authority subordinate to the first mentioned authority.

(2) The following Officers, namely, (1) Director, Radio Construction and Development Unit, (2) Director, Aircraft Inspection, (3) principal, Civil aviation Training Centre, (4) Controller, Central Radio Stores Depot and (5) Deputy Director of Equipment shall come under the jurisdiction of the Regional Director Delhi Region for the purposes of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, who shall exercise the disciplinary powers vested in him in respect of the staff of the said Offices.

[No. C-11011/2/76-EH (4538-VE/77)]
S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1978

व्यापार पोत

का०आ० 2327.—राष्ट्रीय नाविक कल्याण, बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 के खंड (ए) तथा नियम 6 के साथ पठित व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 218 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) भारत सरकार की 29 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना का० आ० 3321 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, क्र० सं० 27 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“श्री एन० पी० जैंगलराया नायडू संसद सदस्य राज्य परिषद (राज्य सभा)”

[एफ० सं० एम डब्ल्यू एम (72)/76-एम टी]

वी० द्वाराकावास, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 28th July, 1978

MERCHANT SHIPPING

S.O. 2327.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 218 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with clause (h) of rule 4 and rule 6 of the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S. O. 3321, dated the 29th September, 1977 namely:—

In the said Notification, for the entry against S. No. 27, the following entry shall be substituted, namely:—

“Shri N. P. Chengalraya Naidu.—Member of Parliament, The Council of States (Rajya Sabha).”

[F. No. MWS(72)/76-MT]

V. DWARAKAVAS, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1978

का०आ० 2328.—अतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार, एतद् उल्लिखित क्षेत्रों के बारे में जो दिनांक 11 फरवरी, 1978 के नोटिस संख्या एक 3 (74)/76-एम० पी० के साथ छापे गए थे, केन्द्रीय सरकार दिल्ली को बृहत् योजना में कतिपय संशोधन करना चाहती है और इसके लिए उसने उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) द्वारा प्रेषित आपत्तियों तथा सुझाव मांगे थे जिन्हें उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर दिया जाना था, और यतः केन्द्रीय सरकारने एतद् उल्लिखित उक्त संशोधन के बारे में आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद दिल्ली को बृहत् योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है,

अतः, अथ, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तारीख से दिल्ली को उक्त बृहत् योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

संशोधन:

“6.7 हेक्टेयर (16.6 एकड़) का क्षेत्र जो पूर्व में 91.4 मीटर (300 चौड़ी) एन० एच० संख्या 8 (दिल्ली गुरुगांव सड़क) समालका ग्राम आबादी के सामने स्थित है, का भूमि उपयोग “कृषि हरित पट्टी” से “औद्योगिक उपयोग” हल्के प्रकार के उत्पादन (ट्रक मरम्मत वर्कशॉप/वर्कशॉप समूह) में परिवर्तित कर दिया गया है।”

[सं० के-13011/2/77-यू० डी०-1(ए)]

हरी राम गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Delhi Division)

New Delhi, the 1st August, 1978

S.O. 2328.—Whereas certain modification which the Central Government propose to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, was published with Notice No. F. 3(74)/76-MP, dated the 11th February, 1978 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice:

And, whereas, the Central Government after considering the objections and suggestions with regard to the said modification mentioned hereunder, have decided to modify the Master Plan for Delhi:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby make the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely:

MODIFICATION:

“The land use of an area measuring 6.7 hec. (16.6 acres) located in the east of 31.4 mts. (300 ft. wide) N. H. No. 8 (Dehi-Gurgaon Road), opposite Samalka Village abadi is changed from ‘Agricultural Green Belt’ to ‘Industrial use’—light manufacturing (truck-repair workshop/shopping complex).”

[No. K-13011/2/72-UDI(A)]

H. R. GOEL, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1978

का०आ० 2329.—अनुच्छेद (ट) के साथ पठित नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 2 के अनुच्छेद (घ) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17 फरवरी, 1976 के एस० पी० सं० (119) ई. की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 5 और 11 और उससे संबंधित इन्दराओं के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित इन्दराओं क्रमशः प्रतिस्थापित किए जायेंगे नामतः—

1	2	3
“5. सेना सम्पदा अधिकारी कर्नाटक ग्रंथाल, बंगलौर	बेलगांव छावनी की स्था- अध्याय 3 और अध्याय नीय सीमाओं के भीतर 4 का अनुच्छेद 26 और समस्त क्षेत्र 27.	
2. सेना सम्पदा अधिकारी (नगर भूमि अधिकतम सीमा) पूना	बेलाली छावनी की स्था- अध्याय 3 और अध्याय नीय सीमाओं के भीतर 4 का अनुच्छेद 26 और 27”	

[एफ सं० 1/40/76 यू० सी० यू०]

एस० महादेव अय्यर, उप सचिव

New Delhi, the 2nd August, 1978

S.O. 2329.—In pursuance of the provisions contained in clause (d) of section 2 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976) read with clause (k) thereof, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Works and Housing No. S.O. (119) E, dated the 17th February, 1976, namely :—

In the said notification, for serial Nos. 5 and 11 and the entries relating thereto, the following serial Nos. and entries relating thereto, shall respectively be substituted, namely :—

1	2	3
"5. Military Estate Officer, Entire area Chapter III and Karnataka Circle, Bangalore.	within the local sections 26 and limits of the 27 of Chapter IV Cantonment of Belgaum.	
11. Military Estate Officer, Entire area with- Chapter III and (Urban Land Ceiling), in the local limits sections 26 and of the Canton- 27 of Chapter ment of Deolali IV."		

[F. No. 1/40/76-UCU].
S. MAHADEVA AYYAR, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 78

का.आ. 2330.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में आवासीय भूखण्डों हेतु मान्य क्षेत्रीय विनियमों (जोनिंग रेगुलेशन्स) को संशोधित करने पर विचार कर रही है, जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधनों के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस शायन के 30 दिनों के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 5वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपने आपत्ति या सुझाव दे, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

संशोधन :

मुख्य योजना के क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विनियमों (जोनिंग एण्ड सब-डिविजन रेगुलेशन्स) से सम्बन्धित अध्याय के परिच्छेद 11 (क्षेत्रीय विनियमों) की धारा ए में "क्षेत्रीय उपयोग की आवश्यकताओं की व्यवस्था" के शीर्षक के पैरा 3 में—

पृष्ठ 55 पर सब (बी) "आवासीय उपयोग क्षेत्र" के शीर्षक के अन्तर्गत भूखण्ड पट्टा हेतु सारणी के मद (1) को निम्न प्रकार से रखा जायेगा।

प्रत्येक मंजिल का पट्टा

- (1) (क) 100 वर्ग गज (83.61 ब०मी०) तक 68-2/3 प्रतिशत
(ख) तथा 100 वर्ग गज (83.61 ब०मी०)
से अधिक और 300 वर्ग गज (250.83
ब०मी०) तक 60 प्रतिशत

2. शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अधि में आकर प्रस्तावित संशोधनों का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं. एफ. 3(35)/77-मु०यो०/पा०-I]

कृष्ण प्रताप, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th August, 1978

S.O. 2330.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Zoning Regulations applicable to the residential plots in the Master Plan for Delhi is hereby published for Public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

MODIFICATION :

In paragraph 5, entitled "PROVISIONS REGARDING REQUIREMENTS IN USE ZONES" occurring in Section A (Zoning Regulation) of Chapter II of the text of the Master Plan dealing with the Zoning and Sub-Division Regulations—

At page 55, against item (b) plot coverage under the heading "Residential Use Zone", item at (i) in the table shall be substituted by the following :—

	Coverage on each floor
(i) (a) Upto 100 sq. yds. (83.61 sq. mtrs.).	66 2/3 %
(b) And above 100 sq. yds. (83.61 sq. mtrs.) but not exceeding 300 sq. yds. (250.83 sq. mts.).	60 %

2. The proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days, except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3(35)/77-MP Pt. 1]
KRISHNA PRATAP, Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1978

का. आ. 2331.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिर्देशक ने विजिंहम टेलीफोन केंद्र में दिनांक 16-8-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निर्देश किया है।

[संख्या 5-10/78-पी. एच. बी.]

के. आर. नायर, उप-महानिर्देशक (एम. एम.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 2nd August, 1978

S.O. 2331.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-8-78 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vizhinjam Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-10/78-PHB]

K. R. NAIR, Dy. Director General (MS)

पूरी और पुनर्वास मंत्रालय**(पुनर्वास विभाग)**

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1978

का० भा० 2332.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हरियाणा राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग में उप-सचिव (पुनर्वास) के रूप में कार्य कर रहे श्री डी०पी० गुप्ता को, उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा ऐसे सहायक महा अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, तत्काल प्रभाव से, निष्क्रान्त सम्पत्ति के सहायक महा अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है। इससे दिनांक 27 जनवरी 1978 की अधिसूचना संख्या 1(8)/विशेष सैल/77-एस०एस०-II का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं० 1(8)/विशेष सैल/77-एस०एस०-II]

दीना नाथ असीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION**(Department of Rehabilitation)**

New Delhi, the 20th July, 1978

S.O. 2332.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950) the Central Government hereby appoints Shri D. P. Gupta, Deputy Secretary (Rehabilitation) in the Rehabilitation Department of the State Government of Haryana, as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Assistant Custodian General by or under the said Act with immediate effect. This supersedes the notification No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS.II dated 27th January, 78.

[No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS. II]

D. N. ASIJA, Jt. Director

का० भा० 2333.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की धारा 3 द्वारा महा अभिरक्षक के रूप में मुझे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, इसके द्वारा इस विभाग की दिनांक 20-7-78 की अधिसूचना संख्या 1(8)/विशेष सैल/77-एस०एस०-II द्वारा नियुक्त हरियाणा राज्य के सहायक महानिरक्षक को महा अभिरक्षक की रिक्त शक्तियां सौंपता हूँ :—

- (i) अधिनियम की धारा 24 और 27 के अधीन शक्तियां।
- (ii) अधिनियम की धारा 10(2) (0) के अधीन किसी भी निष्क्रान्त सम्पत्ति के हस्तारपत्रण के अनुमोदन की शक्तियां।
- (iii) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियम, 1955 के नियम 30-क के अधीन मामलों के हस्तारपत्रण की शक्ति।

इससे दिनांक 27-1-78 की अधिसूचना संख्या 1(8)/विशेष सैल/77-एस० एस० II का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं० 1(8)/विशेष सैल/77-एस०एस०-II]

के० डी० सेनन, महा अभिरक्षक

S.O. 2333.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by sub-section 3 of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I do hereby delegate to the Assistant Custodian General for the State of Haryana, appointed vide this Department's notification No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS.II, dated the 20-7-1978, the following powers of the Custodian General :—

- (i) Powers under Section 24 and 27 of the Act,

456 G I/78—4

(ii) Powers of approval of transfer of any evacuee property under Section 10(2) (o) of the Act.

(iii) Power of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1955.

This supersedes notification No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS. II, dated 27-1-78.

[No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS. II]

K. D. MENON, Custodian General.

श्रम मंत्रालय**प्रदेश**

नई दिल्ली, 31 मई, 1978

का० भा० 2334.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाखंड अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय खाद्य निगम, सत्तनापल्ली की माईन राइस मिल के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्बंधित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के०पी० नारायण राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद की उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्बंधित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय खाद्य निगम सत्तनापल्ली की माईन राइस मिल के कर्मचारों की मातानुपाती दर और कालानुपाती दर काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी-बंदों में संशोधन की मांगों न्यायोचित है? यदि हाँ, तो उक्त कर्मकार किस अनुसंधान के द्वारार है?

[सं० एल-42011/17/77-डी-II की]

हरबंस बहादुर, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR**ORDER**

New Delhi, the 31st May, 1978

S.O. 2334.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Sattenapalli, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. P. Narayana Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen of the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Sattenapalli, for revision of wages of piece rated and time rated workers, is justified? If so, to what relief are the said workers entitled?

[No. L-42011(17)/77-D. II(B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer.

New Delhi, the 27th July, 1978

S.O. 2335.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust, Bombay and their workman which was received by the Central Government on the 25th July, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. CGIT-16 of 1977

Employers in relation to Bombay Port Trust, Bombay

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the employers.—Shri R. K. Shetty, Legal Adviser.

For the workman.—Miss Indira Jaisingh, Advocate.

INDUSTRY: Port & Dock.

STATE: Maharashtra.

Bombay, the 15th July, 1978

AWARD

1. The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal by their order dated 20-7-1977.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bombay Port Trust, Bombay in discharging Shri Anant Arjun Kharde, Clerk Grade II, Docks, from service with effect from the 10th July, 1975 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. Shri Anant Arjun Kharde was initially employed as Marker under the Bombay Port Trust with effect from 1-2-1954 and later he was promoted as Sorter with effect from 4-5-1955. Since 1-8-1955 he has been working as a Tally Clerk and was absorbed in the permanent cadre with effect from 1-4-1956.

3. The above workman was arrested by the Matunga Police Station on the ground that as a result of raid conducted in the laundry of the workman some property, which belongs to the Bombay Port Trust and which was suspected to have been stolen from the Docks of the Port, was recovered from there. For this the workman could not give any explanation. Accordingly two cases, namely 2307/P and 2308/P of 1969 both under Section 381 of the I.P.C. and Section 124 of the Bombay Police Act, were filed against the workman. Judgement in the first case was given on 29-9-1970 and in the second case on 19-10-1970. On a perusal of the judgement in case Nos. 2307/P and 2308/P of 1969 it was found that some items of the Bombay Port Trust stationery were found at the residence/laundry of the workman and, as such, there was a strong ground to commence departmental proceeding against him, for which he was served a charge-sheet dated 8-10-1971. The workman was also suspended with effect from 17-8-1968. He was acquitted in the above two cases. The three charges framed against him were as follows:—

"CHARGE No. I

That Shri Anant Arjun Kharade, Clerk, IInd Grade, Docks Department, Bombay Port Trust, during the period of service in the Bombay Port Trust from 1-2-1954 till date, had committed theft, inter-alia of the following articles belonging to the Bombay Port Trust.

1. 2 ruled exercise books each with size of 8" x 6" and having 200 pages.
2. 2 Bombay Port Trust Ledgers each having 300 pages and bearing No. D. 481-B printed at the WPP-789-100 books 12—60.

3. Bombay Port Trust Padlock, 4 lever, Set No. 2. made in Aligarh in the year 1956.
4. 26 Blue and Red Accountants' Pencils.
5. 18 superior copy pencils.
6. 21 accounting B.P.T. Pencils.
7. 30 pencils of the Bombay Port Trust;

and has thus committed the misconduct of theft of the property belonging to the Bombay Port Trust and has accordingly rendered himself liable to be proceeded against departmentally.

CHARGE No. II

That Shri Anant Arjun Kharade, Clerk 2nd Grade, Docks Department, Bombay Port Trust, was in the habit of misusing stationery belonging to the Bombay Port Trust. Shri A. A. Kharade used Bombay Port Trust Stationery for writing his personal notes and accounts. The particulars of the said stationery are furnished below:—

1. Form for alphabeticized details of the Manifest showing weight bearing No. D. 327-F.
2. Bombay Port Trust Docks Railway Loading Sheets Nos. 40, 31, 64, 78, 61, 68, 64, 32, 7 and 75.
3. Form for record of time shore labour No. 66 bearing No. D 669 F Blocks.
4. Three Bombay Port Trust Railway Loading sheets with their heading cut off containing the scribbles in the handwriting of Shri Anant Arjun Kharade, 2nd Grade Clerk, Docks Department, Bombay Port Trust.
5. 2 ruled exercise books each with the size of 8" x 6" and having 200 pages.
6. 2 Bombay Port Trust Ledgers each having 300 pages and bearing No. 481 B, printed at the WPP—789—100 books 12—60.

Shri Kharade has thus committed the misconduct of causing loss or damage to the Bombay Port Trust property and has accordingly rendered himself liable to be proceeded against departmentally.

CHARGE No. III

That Shri Anant Arjun Kharade, IInd Grade Clerk, Docks Department, Bombay Port Trust, while being an employee of the Bombay Port Trust had been conducting the business of laundry in the name and style of 'Vibgyor Cleaners/Sangam Cleaners' at 'Yakshini Niketan', Azad Road, Andheri (East), Bombay-69 from the year 1961 till date contrary to para 8 of App. B. to the B.P.T. Digest of Pay and Allowances etc. Shri Kharade has thus committed the misconduct of acting contrary to the said provision of the Digest and has accordingly rendered himself liable to be proceeded against departmentally."

The Enquiry Officer held him not guilty in respect of Charge No. 1 and held him guilty in respect of Charge No. 2 & 3. Upon receipt of the Enquiry Report the Docks Manager accepted the findings of the Enquiry Officer and issued a show-cause memo to the workman as to why he should not be discharged. On having found the explanation to the show-cause not satisfactory the Docks' Manager discharged him from service with effect from 10-7-1975 subject to the payment of two months' wages and subject to the approval of this Tribunal in accordance with Section 33C(2)(b) of the I. D. Act, 1947.

4. As such an application under Section 33C(2)(b) was filed before this Court and by Order dated 4-8-1976 my predecessor-in-office agreed with the finding of the Enquiring Officer in respect of item Nos. 1 to 4 and disagreed in respect of item Nos. 5 & 6 set out in Charge No. II, Regarding Charge No. III his finding was that the respondent had not

violated article 8 of Appendix 'B' to the B.P.T. Digest of Pay and Allowances. He concluded by making the following remark :—

"15. The respondent was served with suspension order on 13-8-1968 and the charge-sheet was served on him only on 8-10-1971, although the respondent was acquitted by the Presidency Magistrate, 12th Court, Bandra, Bombay on 29-9-1970. No explanation satisfactory or otherwise was offered to this Tribunal for this inordinate delay in serving the charge-sheet, and conducting the enquiry and the final discharge from service on 10-7-1975. The Damocles sword kept hanging over the head of the respondent, since 13-8-1968. It is really very serious matter which deserves the attention of higher authorities, which to my mind was unnecessary harassment. I very reluctantly approve the action of the applicants in discharging the respondent on the charge of using Bombay Port Trust forms for private purpose, which appears to be a trifle charge.

16. In the circumstances, I strongly recommend the case of the respondent to the applicants for reconsideration. Had it been a reference under Section 10 of the I. D. Act, I would have indeed interfered with the punishment, but I am helpless in the matter as it is only an application under Section 33(2)(b) of the I.D. Act."

The Port Trust Authorities, however, did not consider it a case where lenient view should be taken of the matter and ultimately the present Reference to this Tribunal.

5. A statement of claim has been filed on behalf of the workman which contains many facts which are not quite relevant for the purposes of this case. I shall refer to only those which are of relevance. It is contended therein that the suspension order passed against the workman was vague, untenable, wrong and false as there was no specific incident of a criminal offence alleged against him. It further says that the two Criminal Complaints No. 2307/P and 2308/P of 1969 were filed on a complaint made by Shri S. S. Mathkar, a laundry servant, and his elder brother who were proved to be revengeful against the workman. Shri S. S. Mathkar, who was a Laundry Servant to Shri Tembe who was running the laundry since about 1964, had made a complaint to the Andheri Police Station that he was wrongfully restrained to enter the laundry by the workman and, accordingly, Criminal Case No. 82/P of 1970 under Section 341 of the I.P.C. was started against him. He was however, acquitted on 17-12-1970. On receipt of the Order dated 29-9-1970 in two cases Nos. 2307/P and 2308/P of 1969 from the Presidency Magistrate, 12th Court, Bandra, the workman informed the Docks Manager, B.P.T., by his letter dated 6-10-1970 that he had been acquitted on 29-9-1970. On receipt of this information the Docks Manager was to terminate the suspension order and to treat him on his earned leave, but he did not do so. It shows the ulterior motive and mala fide intention of the Docks Manager. The Docks Manager did not cancel the suspension order; instead started a departmental enquiry against the workman. It was as a result of the activities of Shri S. S. Mathkar and the brothers of the workman as well as the Dock's Officials. There had been about 800 Tally Clerks in the Docks Department, but no Tally Clerk was supplied any stationery or pencils and they were using their own pencils purchased by them. The details as to how the land was acquired and the rooms of the laundry constructed have been given out. The case is that this belonged to his father who gave the property to the workman. Accordingly, his brothers were prejudiced against him and attempted to harass and annoy him by some way or the other. The cottage had four rooms and it was named as "Yakshini Niketan". In one of the four rooms of the Cottage a laundry was started by the father of the workman. It was conducted by his father through lease and licence holders, Shri Kamat and Shri Tembe. After the death of his father, Shri Tembe continued to be the lease and licence holder of the laundry and kept one servant, Shri S. S. Mathkar. This Shri S. S. Mathkar with the help of the workman's brothers is said to have played a havoc against the workman by making complaints to the officials of the Bombay Port Trust and had also filed complaints to the Police Stations at

Matunga and Andheri. The case is that with the conspiracy of Shri S. S. Mathkar and the officials of the Bombay Port Trust some materials might have been arranged in the laundry premises during the suspension period without the workman's knowledge. Shri Anant A. Kharde was not an exclusive owner of the laundry and, therefore, he could not sack Shri S. S. Mathkar who was under the shelter of his brothers and brother-in-law. So far as the departmental enquiry is concerned, it is said that reliance has been placed only on the evidence of the revengeful laundry servant, Shri S. S. Mathkar who had a personal vendetta against the workman. The Enquiry Officer came to the conclusion on the ground that some of the articles found in the laundry bear the handwriting of the workman. No handwriting expert had examined this nor there was any acceptable evidence for coming to this conclusion. The laundry had been started by his father by giving it on a rent of Rs. 30/- per month and it was for the purpose of maintenance of the family, and the workman had no direct concern with this rent. The Rule that "no Officer or servant of the Board shall accept any outside employment of office honorary or otherwise without the previous formal sanction of the Board," is not applicable to the workman as he was not concerned with the laundry business and no financial benefit for his own work was received by him at all. The rent realised was utilised for the family expenses by family members. The workman does not know how the two Registers in question came to the laundry and that there was no reason to discharge the workman with one month's notice.

6. A written statement-cum-rejoinder has been filed on behalf of the Trustees of the Bombay Port Trust, wherein the details of service particulars of the workman have been set out. It is also stated therein that the workman had a very bad record of service in the past and was reduced by 10 places in the register of Tally Clerks as a disciplinary action for his failure to do correct tally since 25 wheat bags were found short in the railway wagon on 15-3-1961. His subsequent service record was equally bad. The employers deny that the suspension order was vague, untenable, wrong and false. They contend that the validity or otherwise of the suspension order is not a matter arising out of the Reference. The workman was arrested by the Matunga Police Station and the information to that effect was sent to the Docks Department, B.P.T. on 3-8-1968. He is said to be in possession of stolen and smuggled article valued at Rs. 10,000 from the Docks. They were found stored in the laundry premises residence at Andheri. The workman could not give any satisfactory explanation about this and, as such, a case was started under Section 381 of the I.P.C. and under Section 124 of the Bombay Police Act. It was on the basis of his report that the workman was suspended with effect from 13-8-1968. While the above matter was still under investigation, the workman was arrested in connection with two more criminal cases Nos. 1050/P/69 and 82/P/70 on 19-10-69 and 10-12-69 respectively. These were under Section 341 of the Indian Penal Code. The judgement in these two cases was delivered on 1-10-70 and 17-12-70 respectively and the copies of the judgments of acquittal were submitted in November, 1970 and January, 1971. On perusal of the Judgement dated 29-9-1970 in case Nos. 2307/P and 2308/P of the 1969, it was found that some items of the B.P.T. stationery were found at the residence stop laundry of the workman. As such there was a strong ground to initiate disciplinary proceedings against him. According a charge-sheet was issued to him on 8-10-71. The continued suspension of the workman was fully justified having regard to the facts and circumstances of the different criminal cases which were going on against the workman in the Criminal Court's. Although the workman had been acquitted by the Criminal Court, it was open to the Employers to proceed against him departmentally and this is what exactly was done in the present case. They deny that there was any ulterior motive and mala fide intention on the part of the Docks Manager in starting departmental proceeding. The workman had been conducting the laundry business contrary to provisions of Article 8 of Appendix 'B' to the B.P.T. Digest of Pay and Allowances, Leave and Pension Rules. It was established in the Domestic Enquiry proceeding that the workman was owing and conducting the business of laundry in the name and style of Vibgyor Cleaners/Sangam Cleaners at Yakshini Niketan at Andheri. With regard to the authenticity of writings of the workman in the various stationery at the vibgy Cleaners/Sangam Cleaners it was easily established by comparison of various hand-writings available to the Enquiry Officer that the workman had, in fact, misused the B.P.T. Stationery. Evidence of handwriting

expert was not at all necessary to come to such a conclusion. If it was the contention of the workman that the handwritings upon the stationery were not his, it was open to him to have applied to the domestic enquiry officer to make a reference to handwriting expert and should have examined himself to deny his own handwriting, but it was not done. The delay in serving charge-sheet to the employee was on account of the fact that the workman was acquitted by the Criminal Court in Case No. 82/P/70 only on 17-12-1970 and he had submitted certified copy of the Judgement by letter dated 18-1-1971. Thereafter the employers had to wait till appeal period was over to avoid any further complication. Subsequently, the Employers wrote to the Deputy Commissioner of Police, Bombay on 10-2-1971 for certified copies of the F.I.R., Panchanama, Statements of witnesses in respect of three cases to institute departmental proceedings. Some documents were received on 7-7-1971 and thereafter the employee was charge-sheeted on 8-10-1971. It is stated that since there was no delay on the part of the Administration in proceeding against the workman departmentally, discharge order is claimed to be fully justified and it is contended that the workman is not entitled to be reinstated in service.

7. Miss Indira Jaisingh, on behalf of the workman, has submitted that the finding of the Domestic Enquiry under Charge No. II is preverse inasmuch as it is not borne out by evidence on record. I shall now refer to the different items under this charge and refer to the evidence on it, and examine whether the finding is borne out by evidence or not.

8. There are six items under Charge No. II. They have already been set out above. Item Nos. 1 to 4 which are sheets and printed forms were collectively marked at the Domestic Enquiry as Ext 16, item No. 5 as Ext. 15 and item No. 6 as Ext. 13. The first witness examined in this regard was Shri D. S. Patkar who was working as Stationery Clerk of the Stationery Section, Indira Dock. He identified them as Port Trust property. He, however, could not testify that these items were actually supplied to the workman concerned. This, is not of any importance since the important question is whether these articles belong to the Port Trust or not, and on this point competency of Shri Patkar cannot be doubted. He has given reasons why he identified them as belonging to the Port Trust. He has stated that notebooks, registers etc. bear the seal of B.P.T. and certain stationeries such as ledgers etc. bear the code numbers starting with letter D. meaning Docks Department. He also identified the registers as Port Trust property bearing Code No. D-481. B.

9. The second witness Shri S. S. Mathkar had identified amongst other things the two ruled Exercise Books (Ext. 15). He was closely connected with the workman in the laundry business. According to him, the workman had started a laundry in 1961 with his brother-in-law (sister's husband) Shri S. D. Naik in the name and style of "Vihgyor Laundry" and the Municipal Licence was in the name of Shri A. A. Kharade. The laundry was subsequently given to one Shri Kamath for running and the name of the laundry was changed to "Sangam Cleaners" and the Municipal licence for the laundry was also changed in favour of Shri M. S. Tembe, a third person, by the workman without informing his partner Shri Naik. Later on, there was a difference of opinion between the workman and Shri Kamath and the laundry was given to the witness for running on payment of Rs. 30 p.m. to the workman. He has deposed that these notebooks etc. were used for the purpose of writing down certain accounts and other particulars and these were written by the workman concerned.

10. Now item No. 6, i.e. two registers (Ext. 13). The enquiring officer has said that these registers bear Code No. D-481-B and on these facts and other evidence he felt satisfied that these registers belonged to the Bombay Port Trust. The forms have been used for the personal purposes by the workman and one form has been used for writing certain accounts. Of the two notebooks (item No. 5) (Ext. 15) one of them has its top label removed and from the other it has been partly removed. He found that there was reasonable ground to believe that they were Port Trust property and that they were used for personal purposes. There are writings on these documents, which have been denied by the workman. The Enquiring Officer compared the writings on these documents

along with the workman's writing available to him and he found that these were written by the workman himself. No doubt, no expert has been examined to prove that these documents contain the handwriting of the workman, but if on a comparison of the handwritings the Enquiring Officer found that the handwritings in question to be of the workman no exception can be taken to it. From the notes of hearing held on 25th February, 1972 at the domestic enquiry, it appears that letters Exts. Nos. 1 to 7 were shown to the workman concerned and he admitted before the Enquiring Officer that the above documents were in his own handwriting. It is clear that the Enquiring Officer had compared the handwritings in question with these documents and found them to be in his handwriting. This he was quite competent to do and to come to his own conclusion regarding the writings. I have looked into the admitted handwritings and to writings on the above documents, and I also agree with the view taken by the Enquiring Officer.

11. Criticism against Shri S. S. Mathkar is that his evidence is not worthy of credence. On 16-12-1970 he along with others had sent a letter to the Docks Manager bringing to his notice that various articles of Bombay Port Trust and stationery have been removed from the Dock's office and are being used by the workman for his personal purposes in the laundry. It was also stated in that letter that on two previous occasions misdeeds of the workman had been discovered, for which he was charge-sheeted and punished. Details of file numbers and dates etc. have been mentioned therein. It has been argued that Shri S. S. Mathkar had close connection with an employee of the Port Trust and from him he obtained these details, otherwise mention thereof could not have been made in the aforesaid letter. This, to my mind, is no ground to throw away his testimony. The letter dated 16-12-1970 was signed by five persons including brother of the workman and his brother-in-law with whom he had litigation as to the ownership of the laundry. It is quite likely that because of the dispute between the workman and his brother and his brother-in-law over the laundry information was given to the police and misdeeds of the workman came to light. After all it is in this manner that some of the crimes see the light of the day. Therefore, I do not feel inclined to throw away the testimony of Shri S. S. Mathkar. In para. 15 of his report, the Enquiring Officer has dealt with this witness. He has stated therein that the motivating force of this witness and others of his camp was not for justice, but the personal vendetta against the workman. The Enquiring Officer could not rely upon him "unless his contentions are corroborated by other independent means a factor which is lacking here." I do not think materials were lacking on record to corroborate Shri S. S. Mathkar when he deposed that these articles belonged to the Port Trust and that the writings upon some of them were of the workman and these articles had been used for his personal purpose. In fact, the Enquiring Officer has already referred to the evidence of Shri D. S. Patkar which amply corroborates evidence of this witness. Therefore, I find no ground to reject his testimony. Thus I find no substance in the argument that the finding of the Enquiry Officer on Charge No. II is not borne out by evidence on record.

12. Now Charge No. III, Para 8 of Appendix 'B' to the B.P.T. Digest of Pay and Allowances, Leave and Pension Rules reads as follows:—

"8. No officer or servant of the Board shall accept any outside employment or office, honorary or otherwise, without the previous formal sanction of the Board."

The finding of the Enquiry Officer is that the laundry belongs to the workman and he received monetary benefit out of it, but he says that "it makes no difference if an employee himself runs a business or gives it out to somebody else to run on a fixed or variable payment. Both the cases attract the provisions of the above Rule of the Digest. The CSE had a business of laundry out of which he used to receive monetary benefit and this he was doing without the sanction of the Board, as required by the above-mentioned provision of the Digest which is applicable to him as an employee of the Bombay Port Trust". According to the available evidence, the workman received monetary benefit of Rs. 30 per month. The Enquiry Officer found him guilty, but remarked that failure to apply for permission was only technical and should not be viewed as a serious misconduct. In my opinion, the

admitted position being that the workman was the proprietor of the laundry, he cannot be deemed to "accept any outside employment or office, honorary or otherwise." A plain reading of Rule 8 of Appendix 'B' to the B.P.T. Digest is sufficient to indicate that it does not contemplate the case of a proprietor. To come within the mischief of Para. 8 the workman should have accepted any outside employment. By being a proprietor, he cannot be deemed to accept any outside employment. Had the intention of para 8 been to include the case of a proprietor, language would have been as is in para. 5. Therefore, I hold that the workman is not guilty of Charge No. III.

13. A great controversy arose between the parties on the suspension order and the consequent subsistence allowance. The Docks Manager passed the suspension order on 13-8-1968 under the Trustees' Resolution No. 404 of 1952. By this order the workman was required to report to the Docks Manager the result of the criminal case. It provided for subsistence grant at the rate mentioned therein during the suspension period. Resolution No. 404 of 1952 has been admitted on behalf of the Management to be a mistake. Despite this, it has been argued for the Management that the power rested with the Docks Manager to place a workman under suspension and to pay subsistence grant. For this purpose reliance has been placed upon Section 23(2) of the Bombay Port Trust Act, 1879 whereby the Chairman may delegate the power to suspend a workman to any head of the Department. Delegation of such a power to the Docks Manager has been done by means of Order dated 15-5-1958. Delegation of power to suspend a workman is subject to the framing of a regulation under Section 22(9) of the B.P.T. Act, 1879. It seems to me the B.P.T. Digest of Pay and Allowances, Leave and Pension Rules must be deemed to be such a regulation. Rule 33 and 34-A, as they existed at the relevant time, provide for a subsistence grant at the rate mentioned therein. In this view of the matter I do not think either suspension or payment of subsistence grant has been contrary to any Rule.

14. It was vehemently argued for the workman that the punishment imposed is disproportionate to the offence of the particular misconduct. The total value of the property of the B.P.T. covered by Charge No. II has been stated by the Criminal Court in one of its judgements as Rs. 30. To deprive a man of livelihood for misuse of property worth Rs. 30 is said to be hard and disproportionate. Reference was made to the fact that the workman continued to be under suspension from 13-8-1968 till he was discharged on 5-7-1975. During this period he was paid subsistence allowance which was a part of the salary. In the two criminal cases he was acquitted on 29-9-1970 and in the third case on 19-10-1970 and in the fourth case on 17-12-1970. But the charge-sheet was issued only on 8-10-1971. There is said to be a great delay in commencing the Domestic Enquiry, with the result that all along he had been suffering a great mental torture and all this for a property worth Rs. 30. While setting out facts of the case I have referred to the case of the Management where it has stated that after the close of the criminal cases attempts were made to get certified copies of various documents and that took some time and that it was because of different criminal cases and the delay in obtaining copies of certain documents that the charge-sheet came to be framed only on 8-10-1971. No doubt, under Section 11-A of the Industrial Disputes Act this Tribunal may vary the punishment imposed. The point for consideration is whether such a discretion is called for. For the Management reference was made to the case of State of Haryana and another V/s. Rattan Singh (1977 Labour & Industrial Cases, page 845) where the Supreme Court did not alter the punishment of termination of service when the employee was held guilty four passengers had alighted from the bus without tickets and 11 passengers travelling in the bus also did not have tickets although they claimed to have paid the fares. I have given my anxious consideration to the question. I find it is not the question of the valuation of the property covered under Charge No. II. But what is of importance is that this was not his first offence. In the letter dated 16-12-1970 sent to the Docks Manager by Shri S. S. Mathkar and others mention has been made of two previous offences and the connected file numbers. The first is B.P.T. File No. ZE/35-A-53/8975 and 6059 of 1960-61 dated 11-3-1961 connected with shortage of some bags of wheat. The workman is said to have been charge-sheeted and punished. The second is File No. ZE/35-A-31/938 of 1962-63 dated 14-5-1962 connected with missing of some rice bags, for which he is said to have been charge-sheeted by an enquiry board and action taken against him. In the written

statement-cum-rejoinder, however, mention has been made of only one disciplinary action for the workman's failure to do the correct tally in that 25 wheat bags were found short in a railway wagon on 15-3-1961 and for which he was reduced by ten places in the register of Tally Clerks. This punishment finds mention also in the statement of charges against the workman concerned. Therefore, this being not the first offence and the punishment imposed being only discharge from service. I do not think that any lenient view should be taken of the matter. The fact that he could not secure any job after termination of service, as deposed to by him, is not calculated to affect the view that I have taken of the matter. I could have persuaded myself to take a lenient view of the matter had this been his first offence. But I find even reduction by ten places produced no salutary effect upon the workman concerned.

15. In the result, my award is that the action of the Management of Bombay Port Trust, Bombay in discharging Shri Anant Arjun Kharde, Clerk Grade II, Docks, from service with effect from the 10th July, 1975 is justified and that he is not entitled to any relief.

16. Reference is answered accordingly.

J. NARAIN, Presiding Officer,
[No. L-31012(5)/77-D-IV (A)]
NAND LAL, Desk Officer,

प्रवेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1978

का० प्रा० 2336.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कारपोरेशन बैंक लिमिटेड, मद्रास के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधि-करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० सेल्वारत्नम होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या श्री धार० विरूपति को, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक मेसर्स कारपोरेशन बैंक लिमिटेड, मद्रास के अधीन ड्राईवर के रूप में नियोजित थे, बैंक के नियमित कर्मचारी के रूप में मानने और इस प्रकार उनके नियमित कर्मचारियों को ग्राह्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होने की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मचारी किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12011/34/78-डी 2-ए]

ORDER

New Delhi, the 29th July 1978

S.O. 2336.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Corporation Bank Ltd., Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A read with clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with

head quarters at Madras, the Presiding Officer of which shall be Shri K. Selvaratnam and refers the said dispute for adjudication to the said Central Government Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand for treating Shri R. Tirupati, employed as Driver under the Regional Manager M/s. Corporation Bank Ltd. Madras as a regular employee of the Bank and as such entitled to pay and allowances admissible to such employees, is justified? If not to what relief is the workman entitled?

[No. L-12011/34/78-D. IIA]

आदेश

कां.प्रा. 2337.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, त्रिचूर के प्रबंधन से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के. सेल्वरत्नम होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, त्रिचूर के अध्यक्ष श्री पी.के. स्वामीनाथन का 1-8-75 से कार चालक के पद पर नियोजित न करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संवन्धित कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है ।

[सं. एल-12011/41/78-डी.ए.2]

ORDER

S.O. 2337.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Dhanalaxmi Bank Ltd., Trichur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sec. 7A read with clause (d) of sub-section (1) of section 19 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer, of which shall be Shri K. Selvaratnam, with head-quarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Central Government Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the Chairman Dhanalaxmi Bank Ltd. Trichur in denying employment to Shri P. K. Swaminathan as Car Driver, with effect from 1-8-75 is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-12011/41/78-D. IIA]

S.O. 2338.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the

Punjab National Bank, M. P. Region, Bhopal and their workmen over transfer of Shri C. M. Kapoor from Raipur to Bina which was received by the Central Government on the 25-7-78.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT. LC(R)(31)/1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen represented through the President, M. P. Bank Employees Association, C/o Punjab National Bank, Jabalpur.

APPEARANCES :

For Association Shri P. N. Sharma, President.
For Bank Shri R. P. Raizada, Senior Personnel Officer.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Raipur (M. P.)

Dated : July 10, 1978

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/99/77-D. II. A Dated 6/14th June, 1978 to this Tribunal for the adjudication of the following dispute :

"Whether the action of the management of Punjab National Bank M. P. Region Bhopal in transferring Shri C. M. Kapoor, General Secretary of M. P. Bank Employees Association Raipur from Raipur to Bina with effect from 7-5-1977 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. Notices were issued to the parties fixing 7-7-1978 for filling their respective written statements. In the meantime they have settled their dispute out of Court. The parties have jointly prayed that since the dispute has already been amicably resolved between them the case be now closed. As the dispute referred to this Tribunal for adjudication has already been settled between the M. P. Bank Employees Association and the Bank a no dispute award is given.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

10-7-1978.

[No. L-12012/99/C177-D. IIA]

New Delhi, the 31st July, 1978

S.O. 2339.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of state Bank of India, New Delhi and their workmen over termination of the services of Shri Y. K. Mittal, permanent clerk which was received by the Central Government on the 28-7-78.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 137 of 1977

In re :

The General Secretary, Delhi Circle State Bank Staff Association, 33, Bank Enclave, Ring Road, Rajouri Garden, New Delhi.Petitioner.

Versus

The State Bank of India, New Delhi Main Branch Post Box. No. 430, New Delhi.Respondent.

PRESENT :

Shri S. Misra, for Bank. None for workmen.

AWARD :

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. I-12012/16/77-D.II. A dated the 2nd June, 1977 made a reference, u/s 10 of the Industrial Act in the following terms to this Tribunal :

"Whether the action of the Management of the State Bank of India, New Delhi Main Branch in terminating the services of Shri Y. K. Mittal a permanent clerk of the Bank w.e.f. 1-8-74 on account of his alleged absence from duty without leave is legal and justified? If not what relief is the workman entitled to?"

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and notices were issued to the respective parties and after the parties appeared a statement of claim was filed on behalf of the workman and the case was adjourned for written statement, but before any written statement could be filed by the Management talks for compromise started between the parties and as such written statement was not filed. Ultimately on the 12th May, 1978 Shri S. Misra appeared for the Bank and stated that a compromise has been arrived at between the parties and he filed a settled Ext. S/1 dated the 6th March, 1978. In pursuance thereof statement of Shri S. Misra was recorded on 12-5-78 in which he stated that the workman has been reinstated as mentioned in the agreement Ex. S/1.

3. From the perusal of the settlement Ext. S/1 I find that certainly the workman has been reinstated and accordingly an award in pursuance of Ex. S/1 is passed in the following terms namely the workman is reinstated and allowed to resume duty at the office from the date he reports for duty and no back wages will be paid to him for the period of his absence from 1st June, 1974 till he is reinstated and the period of his absence will not be counted for the purposes of service, increment, pension, gratuity etc. and the Management will have right to take appropriate action against the workman for his absence under the Shastri or Desai Award and the agreement with the State Bank of India Staff Association. The parties are left to bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[No. L-12012/16/77-D. II. A]

R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1978

कां०प्रा० 2340.—केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (ड) के अनुसरण में, श्री वीरेंद्र सिंह के स्थान पर श्री पी०एस० वबे, अमायुक्त, दिल्ली को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां०प्रा० 1517, तारीख 14 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "(केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (ड) के अधीन संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट" शीर्षक के नीचे मध 28 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"श्री पी०एस० वबे,
अमायुक्त,
दिल्ली प्रशासन,
दिल्ली।"

[संख्या यू०-16012/8/76-एच०प्राई०]

New Delhi, the 29th July, 1978

S.O. 2340.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (e) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri P. S. Dave, Labour Commissioner Delhi to represent the Union Territories on the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri Virendra Singh;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1517, dated the 14th April, 1976, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government under clause (e) of section 4 to represent Union Territories)" for the entry against item 28, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri P. S. Dave,
Labour Commissioner,
Delhi Administration,
Delhi."

[No. U-16012/6/76-HI]

कां०प्रा० 2341.—पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री आर०एन० सेन गुप्ता के स्थान पर श्री ए० चौधरी, सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, कलकत्ता को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां०प्रा० 1517 तारीख 14 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मध 27 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"श्री ए० चौधरी,
सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार,
श्रम विभाग,
कलकत्ता।"

[संख्या यू०-16012(8)/78-एच०प्राई०]

S.O. 2341.—Whereas the State Government of West Bengal has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri A. Chowdhury, Secretary to the Government of West Bengal Labour Department, Calcutta to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri R. N. Sen Gupta;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1517, dated the 14th April, 1976, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 27, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri A. Chowdhury,
Secretary to the Government of West Bengal,
Labour Department,
Calcutta."

[Ni. U-16012/8/76-HI]

कां० 2342.—यतः केरल राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री टी०एन०एन० भट्टाथिरिपद के स्थान पर डा० एम० राघवन, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, केरल सरकार, त्रिवेंद्रम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा प्रसुविधा परिषद्, में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है ;

धतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां० 2980 तारीख 26 जुलाई, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "[सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट] शीर्षक के नीचे मव 12 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

डा० एम० राघवन,
प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
केरल सरकार, त्रिवेंद्रम ।

[सं० यू०-16012/10/78-एच०आई०]
एस० एस० सहस्रनामान, उप-सचिव

S.O. 2342.—Whereas the State Government of Kerala has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Dr. M. Raghavan, Administrative Medical Officer, Employees' State Insurance Scheme, Government of Kerala, Trivandrum, to represent that State on the Medical Benefit Council in place of Shri T. N. N. Bhattachiripad ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2980, dated the 26th July, 1976, namely :—

In the said notification, under the heading "[nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section (1) of section 10]", for the entry against item 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr M. Raghavan,
Administrative Medical Officer,
Employees State Insurance Scheme.
Government of Kerala,
Trivandrum."

[No. U-16012(10)/78-H. I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1978

कां० 2343.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी०बी० रामानाराय को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में दिनांक 2 अगस्त, 1976 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती है ।

[सं० ए०-12025/1/75-खान-I]

कु० मीना गुप्ता, अवसर सचिव

New Delhi, the 29th July, 1978

S.O. 2343.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri V. V. Ramana

Rao as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines with effect from the 2nd August, 1976. (Forenoon).

[F. No. A. 12025/5/75M-M. 1.]

MEENA GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 5th August, 1978

S.O. 2344.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, M.P. Region and their workmen, which was received by the Central Government on the 1-8-78.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL— CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No CGIT/LC(R)(20)/1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank M.P. Region and their workmen represented through the M. P. Bank Employees Association, Yashwant Road, City Post Office Building, Indore (M.P.).

APPEARANCES :

For Union—Shri P. N. Sharma, President.

For Bank—Shri R. P. Raizada.

INDUSTRY : Bank. DISTRICT : Sehore (M.P.).
Dhanbad, the 17th July, 1978

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide order No. L-12012/77-D. II. A dated 12th April, 1978, for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the Regional Manager, (MP Region) Punjab National Bank Bhopal in awarding punishment to Shri A. G. Khan, Clerk-cum-Cashier, Amlaha Branch, Sehore District of stoppage of one graded increment permanently with effect from 16-5-1977 is justified? If not to what relief is the workman entitled?"

2. It is not disputed that Shri A. G. Khan an employee in Amlaha Branch of Punjab National Bank left the office on 8th October, 1974 at about 2.45 p.m. after obtaining the permission of the officer concerned on the ground that he had to take his sick wife to the Doctor for examination. The same day at about 3.30 p.m. he participated in a demonstration and deputation which waited upon Branch Manager of United Commercial Bank at Sehore. At that time the meeting between the Bank Manager and the deputationists did not remain peaceful and consequently the Bank Manager lodged a police report alleging assault, rowdism, manhandling of the Manager and breakage of some Bank property including the mouthpiece of the telephone. Shri Khan is admittedly a member of M.P. Bank Employees Association which had staged that demonstration and deputation. On receiving the report from the Manager of United Commercial Bank the authorities in Punjab National Bank charge-sheeted Shri Khan, Clerk-cum-Cashier at Amlaha Branch of the Bank and the Senior Personnel Officer, Shri R. P. Raizada, held the domestic enquiry. After examining the witnesses on either side he submitted his report on 24th May, 1976. The Regional Manager held that the delinquent participated in the demonstration along with others before the United Commercial Bank at Sehore as a preplanned affair and permission for leaving the headquarters at 2.45 p.m. was obtained primarily for joining hands with the other members responsible for having created an ugly situation in the premises of the United Commercial Bank at Sehore. On these findings he awarded the punishment of deductions of proportionate wages for the period for which permission was obtained to get

his wife checked up at Sehore, and stoppage of one future graded increment permanently. The relevant portions of the charge-sheet framed against Shri A. G. Khan may be reproduced as under :—

"That on 8-10-1974 you left the office at about 2.45 p.m. after obtaining oral permission from the Manager on the plea that your wife was sick and you had to get her examined at the Government Hospital, Sehore, but instead participated in a deputation at the United Commercial Bank, Sehore, whereas per our information an ugly situation cropped up, resulting into damage to the Bank property and manhandling of the Manager."

The charge communicated that this was a major misconduct for which deterrent disciplinary action was called for.

3. There are two aspects of the reference, one is whether the guilt was at all established against the delinquent in the departmental enquiry for which a plea has been raised by the Union that the findings were perverse and the evidence on record did not make out the guilt. The second part of the reference relates to the quantum of punishment. It is said that if such a harsh punishment is given to an employee putting him to a loss of thousands of rupees in the long run simply for participating in legitimate trade union activities that will amount to victimization and should be declared to be grossly disproportionate to the seriousness of the guilt said to be established.

4. Management's case is that Shri Khan was not only a member of the assembly of deputationists or demonstrators which had become violent and hence had become an unlawful assembly, but was also a leader thereof. He himself snatched away telephone from the Manager of United Commercial Bank when the latter was attempting to contact the police. The telephone was thrown away by Shri Khan on the ground resulting in the breakage of its mouth-piece. It is alleged that Shri Khan manhandled and pushed the bank officers who were sitting with the Manager at that time. It was he who caught hold of the hands of the Manager when Shri Shah and others took out their shoes and chappals for making an assault on him. Thus not only an active participation in the assault but also specific illegal acts of violence etc. have been attributed to him.

5. No voice was raised against the fair and impartial nature of the domestic enquiry and admittedly proper opportunity to defend was given to the delinquent. From the punishment aspect the charge can be divided into two parts. The first part relates to the taking of permission to leave the office early under the excuse to take the ailing wife at Sehore to a Doctor there, for which wages of that day have been ordered to be deducted proportionately by way of punishment. The second part is the main incident of participation in the demonstration resulting in an ugly situation, for which one increment has been permanently stopped. As for the first part Shri Khan did obtain permission and left the office at 2.45 p.m. under the plea that his wife was to be got checked by a Doctor. It is not disputed that he took his wife to the Government Doctor, an Assistant Surgeon, and that too at 6.30 p.m. that day. If the intention was to take the wife to the Government Doctor it was obvious that the Government Doctor would not be sitting in the out-door or would not be available in the hospital before 5.30 to 6 p.m. when the normal duty hours in the evening commence. For taking the wife to the Doctor in the evening sitting as an out-door patient it was not necessary to seek permission and leave the Bank at 2.45 p.m. The very fact that the delinquent preferred to participate in the deputation and demonstration after reaching Sehore, indicates that his wife was not seriously ill and there was no emergency to either call the Doctor at the residence or to go and consult him at his residence. This analysis goes to show that permission to leave the office at 2.45 p.m. was taken by Shri Khan only with a view to reach Sehore in time for participating in the deputation or demonstration before the Manager of United Commercial Bank at Sehore. It is pertinent to note that the deputation or demonstration was arranged only after his reaching Sehore. Thus the inference drawn by the Enquiry Officer that Shri Khan took permission to leave the office early at 2.45 p.m. was only for the purpose of participating in the demonstration or deputation before

the Manager of United Commercial Bank at Sehore, appears to be reasonably justified and the punishment of deduction of proportionate wages for that day was the proper order that was passed by the punishing authority.

6. As for the second part the charge of leading the demonstration was never framed against Shri A. G. Khan nor any specific acts were attributed to him in it. The charge was only of participation and as such the evidence of his leadership and about his specific role was not relevant besides being contradictory. It was therefore futile to come to a finding that the acts of leadership and particular roles attributed to Shri Khan in the evidence were not established against him.

7. As for the question of participation, both the management's witnesses and the defence witnesses admitted that when the deputationists entered the cabin of the Manager, the atmosphere inside did not remain peaceful. Loud shoutings etc. were heard outside. Whether the Manager became violent as is alleged by the defence witnesses or the deputationists committed breach of peace inside Manager's cabin, but it was admitted by all that an ugly situation cropped up resulting to the damage in Bank's property and that is the only charge. Thus so far as this charge is concerned admitted position established it.

8. If the members of a peaceful assembly staging a demonstration or taking a deputation to the Manager in his cabin become violent or cross the limits of peaceful representation and discussions, the assembly becomes an unlawful assembly in the eye of law and each member, by his mere presence, becomes vicariously liable for the act of all other members. It is perhaps in this sense that the charge vicariously held the delinquent liable for participation in a deputation/demonstration the result of which was the development of an ugly situation in the Bank premises. It was a clear case of misconduct as it did not remain confined to the normal trade union activities. The Enquiry Officer was therefore right in saying that though the evidence was not sufficient to fix any direct blame on Shri Khan yet as a member of the assembly, whose unlawful and uncalled for activities turned it into an unlawful assembly, he undermined the reputation of the institution he served. I am, therefore, inclined to hold that the findings of the Enquiry Officer are fully supported by the evidence on record and the inferences drawn by him are reasonably correct.

9. This brings me to the question of quantum of punishment. The power to interfere has now vested in the Tribunal by virtue of Section 11A of the Industrial Disputes Act. The delinquent is a member of M.P. Bank Employees Association and for a member it is no crime to participate in a deputation or peaceful demonstration. It is a part of trade union activities. While so participating it is quite possible that the participant may not be in a position to prejudice that the mob will turn violent and a resultant ugly situation would be created. It is in this back ground that a very serious view need not be taken where only vicarious liability arises out of more participation in the demonstration or deputation which was originally peaceful. I am, therefore, of the view that stoppage of one increment permanently causing a loss of thousands of rupees to the workman ultimately may be a punishment leaning towards unjustified harshnesses.

10. Hence the punishment of stoppage of one graded increment permanently is hereby reduced to the stoppage of one graded increment for five years only and that too without affecting the future increments. The other penalty of deduction of proportionate wages for the day on which the delinquent left the office at 2.45 p.m. under a false excuse, is hereby confirmed. Award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer
[No. L-12012/107/77-D. II. A]
R. P. NARULA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आदेश
नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1978

स्टाम्प

क्रा० प्रा० 2345.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उस शुल्क को माफ करती है, जो गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 1975-76 में एक करोड़ रुपये मूल्य के डिबेंचरों के रूप में जारी किए जाने वाले बंध-पत्रों पर और उनके परवर्ती अन्तरण के साक्ष्य रूप दस्तावेजों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[सं० 17/78-स्टाम्प-फा० सं० 33/88/77-वि०फ०]

एम० आर० वैद्य, अधीक्षक सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th August, 1978

ORDER

STAMPS

S.O. 2345.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of debentures to the value of one crore of rupees, floated by the Gujarat Electricity Board in 1975-76 and the documents evidencing subsequent transfers of the same, are chargeable under the said Act.

[No. 17/78-Stamps-F. No. 33/88/77-ST]

M. R. VAIDYA, Under Secy.